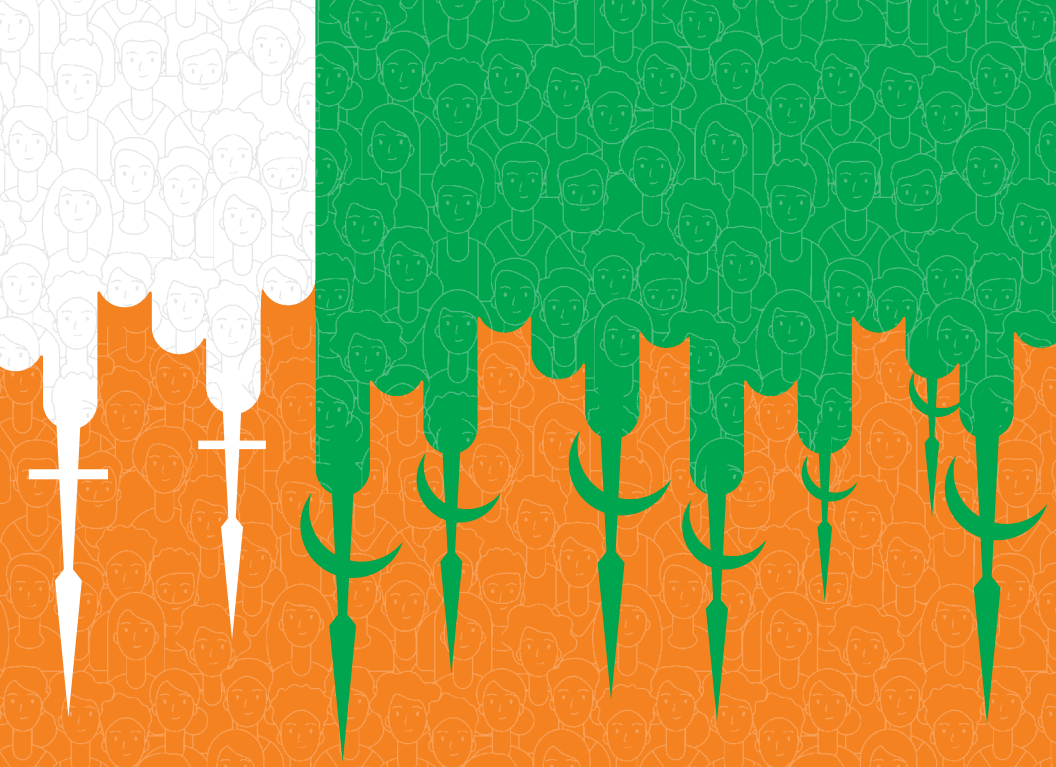

धर्मांतरितों को आरक्षण:

खतरे की घंटी

जे. सत्यजीत

धर्मांतरितों को आरक्षण: खतरे की घंटी

लेखक
जे. सत्यजित

अनुवाद
डॉ. जयश्री टांडेकर

सोशल स्टडीज् फाऊंडेशन

धर्मांतरितों को आरक्षण:

खतरे की घंटी

लेखक : जे. सत्यजित

अनुवाद : डॉ. जयश्री टांडेकर

© : Social Studies Foundation

Email id: ssf@ssfoffice.co.in
संपर्क क्र. – ०२०–२९५२६९७९

प्रकाशक

सोशल स्टडीज् फाउंडेशन
११९६, शिवालय, लिमयेवाडी मार्ग,
भरत नाट्य मंदिर के पास, सदाशिव पेठ
पुणे– ४११०३०

मुखपृष्ट

ईलाइट ग्राफिक्स, पुणे

छपाई

शैलेश आर्ट प्रिन्ट
१३६, नारायण पेठ
पुणे– ४११०३०

मूल्य

रु. ५०/–

प्रथम आवृति

मई २०२३

आईएसबीएन : 978-93-94486-01-0

विषय सुचि

प्रस्तावना	१
परिचय	४
पूर्वपीठिका	१४
जनहित याचिका (पीआईएल) का प्रतिरोध	१८
महत्वपूर्ण न्यायालयीन फैसलें	३१
यह कहाँ लें जाएगा?	४०
उपसंहार	५४

प्रस्तावना

आज की परिस्थिति में हम भारतीयों को कुछ पहलूओ पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन्हें इस प्राचीन राष्ट्र के मौलिक चरित्र और आत्मा को बदलने के लिए एक बड़े डिजाइन के एक छोटे से हिस्से के रूप में आसानी से देखा जा सकता है। इस डिजाइन का मुकाबला करने और राष्ट्रीय हितों और भारत की भौगोलिक अखंडता की रक्षा करने की कार्रवाई के साथ जागरूकता ही एकमात्र समाधान है। इस पुस्तक का उद्देश्य लोगों को एक ऐसे मुद्दे पर जगाना है, जिसे आम आदमी ने गंभीरता से नहीं लिया है। यह मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के बुनियादी सामाजिक ताने–बाने और राष्ट्रीय चरित्र को बदल देगा।

इस मुद्दे में उन लोगों के लिए आरक्षण की मांग शामिल है, जो इस्लाम या ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो गए थे। हालांकि यह मांग कोई नई नहीं है, लेकिन यह एक जनहित याचिका (पीआईएल) के कारण अचानक राष्ट्रीय कार्यसूची पर आ गई है, जिस पर वर्तमान में उच्चतम न्यायालय सुनवाई कर रहा है। जनहित याचिका केंद्र और ईसाई समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संगठनों द्वारा दायर की गई है। जनहित याचिका में उन अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की मांग की गई है जो इस्लाम या ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो गए हैं। केंद्र सरकार ने हलफनामे के जरिए जनहित याचिका में मांग का औपचारिक रूप से विरोध किया है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का भी गठन किया है।

इस मामले का फैसला तो न्यायपालिका करेगी। लेकिन, हर भारतीय को इन पहलूओ को गंभीरता से लेना चाहिए जिससे भविष्य के खतरों को गंभीरता से समझा जा सकता है। भले ही जनहित याचिका में दलील उच्चतम न्यायालय

द्वारा अनुमोदित नहीं है, यह पिछले अनुभव को देखते हुए किसी न किसी रूप में प्रकट होगी। ईसाई और मुसलमान अपनी धार्मिक पहचान से कभी समझौता नहीं करते। यह एक सार्वभौमिक घटना है और भारत तक ही सीमित नहीं है। विद्रोह और धर्मांतरण के कारण छोटे देशों को अपनी राष्ट्रीय पहचान खोने का डर सताता है। उग्रवाद और धर्मांतरण के पीछे की ताकतों को हमेशा उदारवादियों, वामपंथियों और तथाकथित मानवतावादियों द्वारा संरक्षित किया जाता है। जनसंख्या के प्रवाह के कारण कई देशों की जनसांख्यिकी बदल गई है, जिसके परिणामस्वरूप नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं पैदा हो गई हैं।

भारत भी इस घटना से अछूता नहीं है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पंजाब और कश्मीर के सीमावर्ती राज्य समान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बांग्लादेशी या रोहिंग्या द्वारा विद्रोह और ईसाई मिशनरियों द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर धर्मांतरण ने देश के कुछ हिस्सों में जनसांख्यिकी को बदल दिया है। ये क्षेत्र अक्सर कानून और व्यवस्था की समस्या का सामना करते हैं क्योंकि यहाँ मुसलमानों या ईसाइयों का वर्चस्व है और उन्होंने हिंदुओं के प्रति कोई उदार रवैया दिखाने से इनकार कर दिया है। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण लंबे समय से भारत के लिए एक बड़ी समस्या रहा है। भले ही धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून मौजूद है। संविधान के कुछ नियम कानून ऐसे है जो ईसाइयों और इस्लाम के मौलवियों के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते है। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू जनसंख्या घट रही है जबकि मुस्लिम जनसंख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। बौद्धों और सिखों की जनसंख्या में भी गिरावट आ रही है जबकि ईसाई आबादी स्थिर है। हालांकि, ईसाई मिशनरियों ने भ्रामक तरीके अपनाए हैं, जिसके कारण उनकी संख्या बढ़ती तो है, लेकिन वह स्थिर दिखाई देती है।

इस्लाम या ईसाई मत पंथ अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की मांग को बड़े फलक पर देखा जाना चाहिए। यह न केवल उन

अनुसुचित जाति के लोगों के अधिकारों को छीन लेगा, जो अन्य धर्मों में धर्मांतरित नहीं हुए थे, बल्कि राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में कभी न खत्म होने वाली समस्याओं का जन्म होगा। कुछ विद्वानों को डर है कि धर्मांतरित मुसलमानों या ईसाई के लिए आरक्षण से विधायिका में अल्पसंख्यक समुदायों के स्वतंत्रता–पूर्व पृथक प्रतिनिधित्व की मांगों का पुनर्जन्म होगा।

जनहित याचिका के कारण, आरक्षण आधारित धार्मिक भेदभाव जैसे कुछ मूलभूत संवैधानिक मुद्दों को उठाया गया है। इसने मूल संवैधानिक प्रावधान की न्यायिक समीक्षा की भी मांग की है, जो राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन करने का अधिकार देता है। बार–बार संविधान की कसम खाने वाले लोग आज उस जनहित याचिका का समर्थन करते नजर आ रहे हैं जो मूल संवैधानिक प्रावधान की न्यायिक समीक्षा चाहता है। यह संसद के अधिकारों पर न्यायपालिका का अतिक्रमण है। यह बड़ा विरोधाभास है।

यह जनहित याचिका तब दायर की जा रही है जब अल्पसंख्यकों के मूल विचार को लोगों द्वारा चुनौती दी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है – 'अल्पसंख्यक' शब्द की क्या आवश्यकता है जब संविधान धार्मिक भेदभाव को मंजूरी नहीं देता है और कानून के समक्ष सभी को समान मानता है? यह बिल्कुल अनुचित, अतार्किक और अन्यायपूर्ण है कि नागरिकों को एक ओर अल्पसंख्यक होने का लाभ मिलेगा और दूसरी ओर उनकी जाति के कारण भी फ़ायदा मिलेगा। भले ही उनका धर्म जाति को मान्यता न देता हो, परंतु यह हो रहा है। यह पुस्तक इस मुद्दे पर लोगों को जागरुक करने का एक प्रयास है। धर्मांतरित अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की मांग हिमशैल का एक सिरा मात्र है। इन इरादों का अंदाजा कई अन्य कार्यो से लगाया जा सकता है। हम आग्रह करते हैं कि लोग इस पुस्तक के माध्यम से इस मुद्दे को समझें और इसे जन–जन तक ले जाएं। कहा जाता है कि शाश्वत सतर्कता लोकतंत्र की कीमत है। आइए हम सतर्क रहें।

परिचय

अनुसूचित जातियाँ हिंदू समुदाय का एक पिछड़ा वर्ग था, जो अस्पृश्यता की प्रथा के कारण अक्षम थे और अस्पृश्यता की इस बुरी प्रथा को किसी अन्य धर्म द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी और इसलिए हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म से संबंधित अनुसूचित जाति का सवाल ही नहीं उठता था।

यह विचार डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने ४ अप्रैल, १९४९ को संविधान सभा की बैठक में व्यक्त किया था। भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर अपने विचारों को लेकर बहुत स्पष्ट थे। अनुसूचित जातियों पर उनके विचार सुसंगत हैं। डॉ. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दी जो भारत में उत्पन्न हुआ था, और बहुत सोच–समझकर खुद को दो अब्राहिम धर्मों – इस्लाम और ईसाई धर्म से दूर रखा।

डॉ. अम्बेडकर के कथन में तीन बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं १) अनुसूचित जाति हिंदू समुदाय का एक पिछड़ा समुदाय था, जो अस्पृश्यता की प्रथा से अक्षम हो गया था। २) अस्पृश्यता को हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। ३) डॉ. अम्बेडकर ने हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म से संबंधित अनुसूचित जातियों को शामिल करने को बहुत स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। डॉ. अम्बेडकर ने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के चंगुल से अनुसूचित जाति के लोगों की मुक्ति और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी लड़ाई के लिए संविधान एक प्रमुख उपकरण था। जब संविधान की व्याख्या की बात होती है तो उनके विचार एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। डॉ. अम्बेडकर की सोच स्पष्ट थी कि आरक्षण हिंदु समाज के अनुसूचित जाति के लोगों तक ही सीमित होना चाहिए, जो अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के शिकार थे। दूसरे शब्दों में, उनका विचार था कि आरक्षण किसी अन्य धर्म के लिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अन्य धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। आरक्षण

स्वतंत्र भारत की एक प्रमुख विशेषता है, जो विशेष रूप से हिंदू धर्म से संबंधित अनुसूचित जाति के लिए निर्मित किया गया है। हालाँकि, यही नीति स्वतंत्रता–पूर्व युग में भी अपनाई गई थी जब आरक्षण नीति अधिनियमित की गई थी। १९०२ में, राजर्षि शाहू महाराज ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर रियासत में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की शुरुआत की। राजर्षि शाहू महाराज को आरक्षण की अवधारणा का जनक माना जाता है। मैसूर दूसरा राज्य था, जिसने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण लागू किया। १९२१ में लिए गए इस फैसले का श्रेय कृष्णराज वाडियार को जाता है। मद्रास प्रेसीडेंसी ने १९२७ में इसी तरह का निर्णय लिया जब उसने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का विकल्प चुनने का फै सला किया। पेरियार स्वामी ने तब इस मुद्दे पर एक आंदोलन शुरू किया था, जबकि जस्टिस पार्टी के पनागल के राजा तत्कालीन मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री थे।

स्वतंत्रता–पूर्व युग में तीनों उदाहरण से संबंधित आरक्षण हिंदुओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए बनाए गए थे, जो पीढ़ियों से अस्पृश्यता की प्रथा के कारण पीड़ित थे। इनमें से किसी भी फैसले में उन अनुसूचित जाति के लोगों का जिक्र नहीं है, जो मुख्य रूप से इस्लाम और ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो गए थे। वास्तव में, यह मुद्दा उनके एजेंडे में भी नहीं था जब इस्लाम और ईसाई धर्म में धर्मांतरण भारतीय सामाजिक जीवन की एक वास्तविकता थी। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि आरक्षण नीति ऐतिहासिक रूप से केवल हिंदू समाज के पिछडे वर्ग के लोगों के लिए है और अन्य लोग इसका दावा नहीं कर सकते हैं।

आगामी घटनाक्रम – ब्रिटिश शासन की अवधि के दौरान भी – इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि आरक्षण नीति अनिवार्य रूप से हिंदू समाज के अंतर्गत दबे हुए वर्ग के लोगों के लिए थी। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग पहली बार भारत सरकार अधिनियम, १९३५ में किया गया। इस अधिनियम ने अनुसूचित

जातियों को ऐसी जातियों, नस्लों या जनजातियों या जातियों, नस्लों या जनजातियों के भीतर के समूहों या समूहों के रूप में परिभाषित किया, जो जाति, नस्ल, जनजाति के हिस्से या समूह हैं, जो परिषद में महामहिम के वर्गों के अनुरूप प्रतीत होते हैं। इस अधिनियम ने अनुसूचित जातियों को ऐसी जातियों, नस्लों या जनजातियों या जातियों, नस्लों या जनजातियों के समूहों के रूप में परिभाषित किया, जो परिषद में महामहिम को प्रतीत होता है कि वे व्यक्तियों के वर्गों के अनुरूप हैं जिन्हें पहले उदास वर्गों के रूप में जाना जाता था, जैसा कि परिषद में महामहिम निर्दिष्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात, भारत सरकार ने १९३६ में एक आदेश जारी किया, जिसमें कुछ जातियों और जनजातियों को अनुसूचित सूची में निर्दिष्ट किया गया। परिभाषा और सरकारी आदेश एक बार फिर यह दर्शाते है कि आरक्षण के लिए धर्म नहीं केवल जाति की आवश्यकता है। इसने रेखांकित किया कि मूल रूप से आरक्षण हिंदू समाज में वंचित लोगों के कल्याण के लिए लक्षित है।

भारत में उपेक्षित लोगों की पहचान करने का पहला प्रयास १९३१ की जनगणना के दौरान किया गया था। तत्कालीन जनगणना आयुक्त ने आदेश में 'डिप्रेस्ड वर्ग' शब्द का प्रयोग किया था। आदेश स्व–व्याख्यात्मक है क्योंकि यह पुष्टि करता है कि यह अभ्यास हिंदू समाज में कमजोर लोगों के लिए है। जनगणना आयुक्त के आदेश में कहा गया है, ''मैंने डिप्रेस्ड जातियों को जातियों के रूप में समझाया है, जिनके संपर्क में आने से उच्च जाति के हिंदुओं के शुद्धिकरण की जरूरत पर जोर दिया गया है। यह इरादा नहीं है कि इस शब्द का व्यवसाय के रूप में कोई संदर्भ होना चाहिए, लेकिन उन जातियों के लिए है, जो हिंदू समाज में अपनी पारंपरिक स्थिति के कारण मंदिरों तक पहुंच से वंचित हैं, उदाहरण के लिए, या उन्हें अलग कुओं का उपयोग करना पड़ता है या उन्हें स्कूल के अंदर बैठने की अनुमति नहीं होती है लेकिन उन्हें बाहर रहना पड़ता है या समान सामाजिक अक्षमताओं का सामना करना पड़ता है।'' यह आदेश स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह केवल हिंदू समाज पर केंद्रित है, जो

अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव से विकलांग था।
जनगणना आयुक्त ने डिप्रेस्ड वर्ग के लोगों की पहचान के लिए नौ परीक्षणों को अपनाया। उक्त आदेश में नौ बार 'जाति' शब्द का प्रयोग हुआ है जबकि 'हिन्दू' शब्द का चार बार प्रयोग हुआ है। इसमें न तो हिंदू के अलावा किसी धर्म का जिक्र है और न ही धर्मांतरित लोगों का। इसने फिर से इस बात पर जोर दिया कि डिप्रेस्ड वर्ग के लोगों की पहचान करने के लिए जाति सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। यह बात महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य है कि भारत सरकार (अनुसूचित जाति) आदेश, १९३६, जो डिप्रेस्ड वर्गों की पिछली सूची की निरंतरता था, कहता है, ''किसी भी भारतीय ईसाई को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा।''

संविधान निर्माताओं की दृष्टि को समझने के लिए अक्सर संविधान सभा में चर्चा का उल्लेख किया जाता है। यह संविधान की भावना और उसके मूल्यों को समझने में मदद करता है। संविधान सभा की बैठकों में अल्पसंख्यक अधिकारों, उनके प्रतिनिधित्व और स्वतंत्रता के विषयों पर चर्चा की गई। लेकिन धर्मांतरित लोगों के लिए आरक्षण का कोई संदर्भ नहीं मिलता है। इससे एक बार फिर साबित होता है कि संविधान निर्माताओं ने धर्मांतरित लोगों को आरक्षण देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग पूरी संविधान सभा, जिसमें मुसलमानों और ईसाइयों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, इस विषय को संबोधित न करने पर एकमत थे। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वे केवल हिंदू समाज के पिछडे वर्ग के लोगों को ही आरक्षण देने पर एकमत थे, जो अस्पृश्यता से प्रभावित थे।

डॉ. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की मुखरता से मांग की। उन्होंने ४ अप्रैल, १९४९ को संविधान सभा में कहा, ''अनुसूचित जातियां हिंदू समुदाय के पिछड़े वर्ग थे, जो अस्पृश्यता के प्रथा से विकलांग थे और अस्पृश्यता की इस बुरी प्रथा को किसी अन्य धर्म द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी और इसलिए हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म से संबंधित अनुसूचित जाति

का सवाल ही नहीं उठता था।'' इसका तात्पर्य एक मूलभूत तथ्य से है कि अस्पृश्यता हिंदू समुदाय तक ही सीमित है और हिंदुओं के अलावा अन्य धर्म अस्पृश्यता को मान्यता नहीं देते हैं।

संविधान सभा ने मुस्लिम समुदाय को शामिल करते हुए चर्चा के लिए अंदाज़न तौर पर चार विषयों की पहचान की थी। अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधायिका में प्रतिनिधित्व, कैबिनेट में आरक्षण, सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण और प्रशासनिक तंत्र जैसे विषयों को शामिल किया। हालाँकि, बहस और चर्चा का पूरा ध्यान विधायिका में प्रतिनिधित्व पर था। राजनीतिक प्रतिनिधित्व मुसलमानों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता थी और उन्होंने धर्मांतरित मुसलमानों के लिए आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एन वी गाडगिल ने अपनी पुस्तक – गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड – में बताया है कि कैसे मुसलमानों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए पंडित नेहरू दबाव में थे। गाडगिल ने अपनी पुस्तक में कहा है कि लियाकत अली मार्च १९५० में – आजादी के तीन साल बाद – विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के लिए पंडित नेहरू से अनुरोध करने के लिए दिल्ली आए थे। गाडगिल ने आगे कहा कि लियाकत अली की मांग को पंडित नेहरू ने स्वीकार कर लिया था लेकिन कैबिनेट ने इसे ठुकरा दिया था। इस घटना से साबित होता है कि मुसलमान सामाजिक क्षेत्र में आरक्षण के स्थान पर राजनीतिक आरक्षण प्राप्त करने के लिए अधिक उत्सुक थे।

विद्वानों ने इस मुद्दे पर मुसलमानों और ईसाइयों के प्रतिनिधियों की चुप्पी को समझने की कोशिश की है। १९३६ के सरकारी आदेश को ईसाई समुदाय की चुप्पी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। आदेश में विशेष रूप से कहा गया है, कोई भी भारतीय ईसाई अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। यह आदेश ब्रिटिश शासन द्वारा जारी किया गया था, जिसकी ईसाई धर्म के प्रति गहरी सहानुभूति थी। ईसाई मिशनरियों ने कई मौकों पर घोषणा की थी कि

उनके धर्म में छुआछूत या जातिगत भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं थी। परिणामस्वरूप, धर्मांतरित ईसाइयों के लिए आरक्षण का विषय नहीं उठाया गया। इसी तरह, संविधान सभा में मुस्लिम प्रतिनिधि आरक्षण पाने के इच्छुक नहीं थे। वे विधायिका में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए अधिक आग्रही थे, जिसकी कड़ी आलोचना की गई क्योंकि यह अखंड भारत के सिद्धांत के विरुद्ध था। वास्तव में, तजामुल हुसैन, जो बिहार से कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, ने आरक्षण के विचार का घोर विरोध किया था। मुसलमान राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अधिक रुचि रखते थे, समुदाय में इस आधार पर आरक्षण के खिलाफ तीव्र आक्रोश था क्योंकि इससे उनके धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप होता।

हालाँकि, सिखों और बौद्धों के बारे में ऐसा नहीं था। सरदार पटेल ने स्वीकार किया था कि हिंदुओं की तरह सिख भी कई तरह की अक्षमताओं से पीड़ित थे। सरदार पटेल को अकाली दल के हुकुम सिंह का समर्थन प्राप्त था। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्नल बी एच जैदी ने भी बौद्ध धर्म के बारे में इसी तरह की भावना व्यक्त की थी। इस्लाम और ईसाई धर्म के विपरीत, सिखों और बौद्धों की भावनाओं को संविधान सभा में उठाया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिख और बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय मिट्टी में हुआ हैं और गैर–अब्राहिम हैं। संविधान सभा में बहस से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह उन लोगों को आरक्षण देने के लिए कभी उत्सुक नहीं था, जो इस्लाम या ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो गए थे।

आजादी के बाद संविधान लागू होने के बाद अनुसूचित जातियों की यही परिभाषा बरकरार रखी गई। संविधान के अनुच्छेद ३६६ ने यह परिभाषा दी थी, जिसमें यह प्रतिबिंबित था कि न तो संविधान निर्माताओं और न ही सत्तारूढ़ दल ने आरक्षण के केंद्र को बदलने की जरूरत महसूस की। अनुच्छेद ३६६ कहता है, अनुसूचित जाति का अर्थ ऐसे मामले, नस्ल या जनजाति या ऐसी जातियों, नस्लों या जनजातियों के समूह से हैं जिन्हें अनुच्छेद ३४१ के तहत

इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जाति माना जाता हो। इन अनुच्छेद ने पहले सर्वसम्मत निर्णय को जारी रखा, जिसमें हिंदू समाज में जाति को आरक्षण के लिए एक आवश्यक तत्व था। संविधान के अनुच्छेद ३४१ में अनुसूचित जातियों की सूची में परिवर्तन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यह अनुच्छेद संसद और राष्ट्रपति को ऐसी कोई भी कवायद करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद ३४१ में भी विशेष रूप से जातियों और जनजातियों का उल्लेख है। यह अनुच्छेद संसद और राष्ट्रपति को ऐसी कोई भी साहय करने के लिए सशक्त करता है। अनुच्छेद ३४१ में भी विशेष रूप से जातियों और जनजातियों का उल्लेख मिलता है।

१९०२ से आजादी तक आरक्षण का इतिहास, संविधान निर्माण की प्रक्रिया सहित, स्पष्ट रूप से बताता है कि धर्मांतरित मुसलमानों और ईसाइयों के लिए आरक्षण कभी भी कार्यसूची में नहीं था। यह हिंदू समुदाय तक ही सीमित था, जो अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव से प्रभावित था। जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तब न तो मुसलमानों और न ही ईसाइयों ने ऐसी कोई मांग की थी। जातिगत भेदभाव या छुआछूत आरक्षण का एकमात्र मानदंड था और इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुयायी इस श्रेणी के लिए योग्य नहीं थे क्योंकि दोनों धर्मों में जाति का कोई स्थान नहीं है।

१९५० के बाद से, राष्ट्रपति ने अनुसूचित जाति सूची के संबंध में छह आदेश दिए हैं। लेकिन इनमें से दो– १९५६ और १९९० अहम हैं। १९५६ के आदेश में सिख समुदाय शामिल है जबकि १९९० के आदेश का संबंध बौद्धों से है। १९५० में पहला आदेश कहता है, ''कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा।''

१९५७ में, राष्ट्रपति के आदेश ने अनुसूचित जातियों की सूची में सिख धर्म के कुछ वर्गों को शामिल करने के लिए कुछ बदलाव किए। १९५७ के आदेश में

कहा गया है, ''हिंदू धर्म से अलग धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। बशर्ते कि पंजाब या पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ में रहने वाले रामदासी, कबीरपंथी, मजहबी या सिकलीगर जातियों के प्रत्येक सदस्य को उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति का सदस्य माना जाएगा, चाहे वह हिंदू धर्म को मानता हो या सिख धर्म को।''

अनुसूचित जातियों की सूची में यह पहली बड़ी वृद्धि थी। लेकिन १९५३ में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के बाद ही इसे जोड़ा गया था। आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे। आयोग ने सिख समुदाय को जोड़ने के साथ अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन का सुझाव दिया था। तदनुसार, रामदासी, कबीरपंथी, मज़हबी या सिकलीगर समुदायों को शामिल किया गया क्योंकि ये समूह अस्पृश्यता या जातिगत भेदभाव से पीड़ित थे।

१९९० में, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, १९५० में एक और संशोधन किया गया और बौद्ध धर्म को भी अनुसूचित जाति के दायरे में लाया गया। राष्ट्रपति के आदेश, १९९० में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। बौद्धों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करते समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद २५ के तहत स्पष्टीकरण दिया गया था। इसमें लिखा है, ''उपखंड (बी) में हिंदुओं के संदर्भ में सिख, जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के संदर्भ को शामिल किया जाएगा, और हिंदू धार्मिक संस्थानों के संदर्भ को तदनुसार माना जाएगा।''

१९५६ में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के बाद से लंबे समय से चली आ रही मांग के कारण बौद्धों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया था। बौद्ध धर्म को शामिल किया गया था क्योंकि १९५६ का

धर्मांतरण प्रकृति में ईसाई या इस्लाम धर्म की तुलना में भिन्न था। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए आह्वान के जवाब में अनुसूचित जातियों ने स्वेच्छा से बौद्ध धर्म को अपनाया। यह कुछ सहज सामाजिक–राजनीतिक अनिवार्यताओं के कारण मौलिक रूप से भिन्न था। बौद्धों को शामिल करने का समर्थन इस आधार पर भी किया गया था कि बौद्ध धर्मान्तरित की मूल जातियों को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है।

ब्रिटिश शासन के आदेशों को ध्यान में रखते हुए, संविधान सभा में चर्चा, संविधान के प्रवर्तन और उसके बाद के संशोधन से पता चलता है कि हिंदू धर्म में डिप्रेस्ड वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना एक राष्ट्रीय सहमति थी, जो जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता से विकलांग थे। नौ दशकों में विकास की श्रृंखला स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है कि आरक्षण केवल हिंदू समुदाय के उत्पीड़ित लोगों के लिए था। धर्मांतरितों के लिए आरक्षण का विषय नौ दशकों में कभी नहीं उठाया गया।

मार्च १९९६ में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा धर्मांतरित ईसाइयों को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करने का एक गंभीर प्रयास किया गया था। कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एक टिप्पणी में राष्ट्रपति के आदेश, १९५० में संशोधन का प्रस्ताव था, जो इस कदम का मार्ग प्रशस्त करता। यह टिप्पणी ६ मार्च १९९६ को भेजी गई थी जबकि कैबिनेट ने अगले दिन तुरंत इस पर विचार किया।

चीजें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ीं और संसद सत्र में चर्चा के लिए कार्य की पूरक सूची में टिप्पणी को तुरंत शामिल कर लिया गया। हालांकि, धर्मांतरित ईसाइयों को शामिल करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश, १९५० में संशोधन का प्रस्ताव करने वाले बिल को सदन में अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के कारण पेश नहीं किया जा सका।

इस मुद्दे का एक और गंभीर पहलू भी है। भारत के महारजिस्ट्रार और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग ने धर्मांतरित मुसलमानों और ईसाइयों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने से इनकार कर दिया था। भारत के महारजिस्ट्रार ने १४ मार्च, २००१ को इस संबंध में एक आधिकारिक निर्णय लिया था। इसी तरह, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (NCSCST) ने १० अक्टूबर, २००० को धर्मांतरित मुसलमानों और ईसाइयों को सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

पूर्वपीठिका

धर्मांतरित मुसलमानों और ईसाइयों को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने की मांग को उस समय बड़ा बल मिला जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने कुछ ही समय में दो अलग–अलग आयोगों अर्थात समितियों का गठन कर दिया। सबसे पहले, यह राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग था, जिसका नेतृत्व भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा ने किया था। आयोग को रंगनाथ मिश्रा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। मई २००४ में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के पांच महीने बाद २९ अक्टूबर २००४ को इसकी स्थापना की गई थी। आयोग ने मई २००७ में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पर उसकी सिफारिशों की वजह से जमकर हमला हुआ। आयोग पर एकतरफा सिफारिशें करने का आरोप लगा था। मिश्रा आयोग को कांग्रेस की तुष्टिकरण की एक और नीति बताया गया। मिश्रा आयोग की प्रमुख सिफारिशों में मुस्लिमों के लिए दस प्रतिशत कोटा और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए पांच प्रतिशत कोटा के साथ–साथ मुस्लिमों के लिए ओबीसी कोटा में वृद्धि शामिल थी। हालांकि, इसने दो अन्य बड़े सुझाव दिए, जिनकी वजह से आरक्षण का मूल चरित्र बदलना निश्चित था। मिश्रा आयोग ने धर्म को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दर्जे से अलग करने की मांग की और १९५० के राष्ट्रपति के आदेश में आवश्यक संशोधन करने को कहा।

विशेष रूप से इसमें यह भी सुझाव दिया गया था कि जिन अनुसूचित जाति के लोगों ने इस्लाम या ईसाई धर्म को अपना लिया था, उन्हें आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। मिश्रा आयोग की सिफारिशों में से एक अल्पसंख्यकों के लिए १५ प्रतिशत आरक्षण की थी, जिसमें मुसलमानों के लिए विशेष रूप से दस प्रतिशत शामिल था। लेकिन मिश्रा आयोग ने एक कदम आगे

बढ़कर सिफारिश की कि अगर आवश्यक उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे तो बहुसंख्यक समुदाय (हिंदू) के उम्मीदवार की भर्ती नहीं की जानी चाहिए। इसमें सुझाव दिया गया कि अल्पसंख्यकों के लिए १५ प्रतिशत कोटा, अल्पसंख्यक समुदायों से ही भरना होगा। हिंदू स्वाभाविक रूप से सिफारिशों से नाराज हो गए क्योंकि काफी हद तक इसे विस्तारित तुष्टीकरण की नीति के रूप में देखा गया था, और जिससे राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की गई। जब रंगनाथ मिश्रा आयोग काम कर रहा था, तब मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली यूपीए सरकार ने एक और समिति के गठन की घोषणा की। यह समिति विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित की गई थी। न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने १७ नवंबर, २००६ को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। सरकार ने तुरंत ३० नवंबर को संसद में रिपोर्ट पेश की। सच्चर कमेटी की कई सिफारिशों को मुसलमानों के पिछले दरवाजे से प्रवेश के रूप में देखा गया। उदाहरण के लिए, सच्चर समिति ने सार्वजनिक निकायों में अल्पसंख्यकों (मुसलमानों) की भागीदारी बढ़ाने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव दिया।

मिश्रा और सच्चर आयोग दोनों की रिपोर्ट गंभीर हमले की चपेट में आ गई। उनकी रिपोर्ट को बहुत बड़े मंसूबे के हिस्से के रूप में देखा गया था। प्रमुख आपत्ति यह थी कि इस रिपोर्ट से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को जाति के आधार पर और भी बांटा जाएगा और धार्मिक भावनाओं को और भी भड़काया जाएगा। मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पर हमला किया गया क्योंकि उसने बिना किसी वैज्ञानिक और पद्धतिगत अध्ययन किए सिफारिशें कीं, और रिपोर्टों में मौजूदा स्थिति पर संभावित प्रभाव पर विचार नहीं किया गया। आलोचना की गई कि यह रिपोर्ट धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए तैयारी करने की कोशिश कर रही थी। विद्वान ने इस रिपोर्ट को इस्लाम और ईसाई धर्म में जाति को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए आलोचना की हैं, जब दोनों धर्मों में जातियों के लिए कोई स्थान नहीं है।

मिश्रा आयोग को भी चुनौती दी गई। आयोग की सदस्य सचिव आशा दास सिफारिशों से सहमत नहीं हुईं और एक असंतोष नोट संलग्न किया, जो रिपोर्ट का आधिकारिक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पिछडे समुदाय में धर्मान्तरित के विरुद्ध भेदभाव धर्म का आंतरिक मामला है और उन्हें धार्मिक सुधारों या किसी अन्य तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है, और उन धर्मों में जाति व्यवस्था को शामिल करके नहीं जो उन्हें जाति व्यवस्था में शामिल करने के हस्तक्षेप को मान्यता नहीं देते हैं, जिससे उन्होंने एक समतावादी धर्म को अपनाने का विकल्प चुना। दास ने कहा कि परीक्षण अस्पृश्यता के ऐतिहासिक प्रथा से उत्पन्न सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर था।

अस्पृश्यता, अनुसूचित जाति के आर्थिक और शैक्षिक विकास और संबंधित दस्तावेज समिति की रिपोर्ट १९६९, को उद्धृत करते हुए दास ने आगे लिखा, इस प्रकार धर्म १९३६ में और बाद में १९५० में अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों को शामिल करने का आधार था। दास ने आगे कहा, ईसाई या इस्लाम में धर्मांतरित अनुसूचित जाति मूल के लिए आरक्षण के जाल का विस्तार करने का मतलब इन धर्मों के आंतरिक धार्मिक मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होगा क्योंकि वे जातियों को बिल्कुल भी मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए, यह तर्क कि धर्मांतरण के बावजूद इन धर्मांतरणियों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति अपरिवर्तित रही और इसलिए उन्हें भी आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए, उचित नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा ऐसे धर्मांतरण करने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा देना इस्लाम या ईसाई धर्म में जाति प्रणालियों की औपचारिक शुरुआत करना होगा और उनके धर्म के मूल सिद्धांतों को बदलने के समान होगा, जो संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा।

वह तर्क देती है कि इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों ही ऐसे धर्म हैं जो भारत के

बाहर पैदा हुए थे। ये व्यापारी, आक्रमणकारी और प्रचारकों या मिशनरियों के साथ विदेशी भूमि से समय अवधि में भारत आए थे। दोनों ही धर्म जातियों को मान्यता नहीं देते। आज भारत में मुसलमानों और ईसाइयों की एक बड़ी संख्या में धर्मांतरण और उनकी संतान शामिल हैं, और ऐसे मुसलमानों या ईसाइयों की पहचान करना जो मूल रूप से अनुसूचित जाति के थे, कई समस्याओं को उत्पन्न कर देगी क्योंकि इसका कोई प्रामाणिक रिकॉर्ड नहीं रखा गया है।

दास ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुसूचित जाति से ईसाई धर्म और इस्लाम में धर्मांतरित लोगों की पहचान करने के लिए अपनाई गई कोई भी प्रक्रिया वास्तविक योग्य लोगों की पहचान के लिए तर्कसंगत और न्यायसंगत निर्णय लेने के लिए असंख्य जोखिम उत्पन्न करेगी। वह चेतावनी देती है कि दुरुपयोग की संभावना और योग्य की कीमत पर अयोग्य लाभ प्राप्त करने की संभावना जबरदस्त है।

दास के अनुसार, इस तथ्यात्मक स्थिति के मद्देनजर अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा ईसाई और इस्लाम में धर्मांतरण और उन्हें संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश १९५० के परिच्छेद ३ में शामिल करने की मांग, या आदेश से धर्म के संदर्भ को हटा देने की मांग, उचित नहीं है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस विचार को बरकरार रखा है कि कई फैसलों में धर्मान्तरित आरक्षण के योग्य नहीं थे। निःसंदेह, सभी ऐतिहासिक तथ्यों और संविधान के मंशा पर विचार करने के बाद ऐसा हुआ। कई मामलों में, न्यायपालिका ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जाति सामाजिक रूप से बीमार थी, हिंदुओं तक सीमित थी और जाति कभी भी इस्लाम और ईसाई धर्म की विशेषता नहीं थी। दूसरे शब्दों में कहें तो इन दो अब्राहिम धर्मों में आरक्षण कभी उपयुक्त नहीं था।

जनहित याचिका (पीआईएल) का प्रतिरोध

वर्तमान जनहित याचिका की उत्पत्ति बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा २००१ में दिए गए एक फैसले में हुई है, जिसमें उसने एक ऐसे व्यक्ति को अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया था, जो मदारी था और इस्लाम धर्म से संबंधित था। यह मामला गाजी सादुद्दीन और नसीर खान द्वारा दायर एक अपील थी। दोनों ने औरंगाबाद से नगर निगम का चुनाव उन प्रभागों से लड़ा है, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे। उच्च न्यायालय ने संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र पर विचार करने से इनकार कर दिया था। पराजित उम्मीदवार श्री चांदने ने जाति प्रमाण पत्र की वैधता को चुनौती देते हुए पहले जाति सत्यापन समिति का दरवाजा खटखटाया था। समिति ने गाजी सादुद्दीन और नसीर खान को अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में पहचानने से इनकार कर दिया और दोनों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने जाति सत्यापन समिति के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जो अभी भी अनिर्णीत है। कई एनजीओ और अन्य ने बाद में इस मामले में हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने हाथ में लिया। अप्रैल २०२३ में हुई ताजा सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि वह सरकार द्वारा नियुक्त के जी बालाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं करेगा क्योंकि यह मामला दो दशकों से अधिक समय से लंबित है।

रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें अन्य धर्मों में धर्मांतरित अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की मांग की गई है। सीपीआईएल की स्थापना १९८० के दशक में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी एम तारकुंडे द्वारा की गई थी जब संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में भी जनहित याचिका की अवधारणा नई थी। जस्टिस तारकुंडे के

अलावा, फली एस नरीमन और शांति भूषण भी एनजीओ से जुड़े थे। बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर भी एनजीओ से जुड़ गए। वर्तमान में, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण एनजीओ से जुड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए भी उपस्थित हो रहे हैं।

सीपीआईएल के अलावा, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (सीबीसीआई) और नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च ऑफ इंडिया (एनसीसीआई) भी जनहित याचिका में पक्षकार हैं। कैथोलिक बिशप्स एंड कांफ्रेंस ऑफ इंडिया भारत के कैथोलिक बिशप्स का स्थायी संघ है। औपचारिक रूप से सितंबर १९४४ में मद्रास में आयोजित महानगरों के सम्मेलन में इसका गठन किया गया था। सीबीसीआई की वेबसाइट के अनुसार, इसका उद्देश्य चर्च को प्रभावित करने वाले प्रश्नों के समन्वित अध्ययन और चर्चा को सुविधाजनक बनाना और भारत में चर्च के हितों से संबंधित सभी मामलों में एक आम नीति और प्रभावी कार्रवाई को अपनाना है। भारत में चर्चों की राष्ट्रीय परिषद (एनसीसीआई) प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स चर्चों की सर्वोच्च संस्था है। इस परिषद की स्थापना १९१४ में राष्ट्रीय मिशनरी परिषद के रूप में हुई थी। १९२३ में, परिषद ने खुद को भारत की राष्ट्रीय ईसाई परिषद के रूप में गठित किया और १९७९ में परिषद ने खुद को भारत में चर्चों की राष्ट्रीय परिषद के रूप में तब्दील किया। यह परिषद विचार और कार्रवाई के लिए एक सामान्य मंच है और भारत में गिरिजाघर के जीवन और साक्षी से संबंधित सभी मामलों में आपसी परामर्श, सहायता और कार्रवाई के लिए गिरिजाघर और अन्य ईसाई संगठनों को एक साथ लाती है।

इस जनहित याचिका ने संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश १९५० को मौलिक रूप से चुनौती दी है, जिसे समय–समय पर संशोधित किया गया था। जनहित याचिका में कहा गया है कि यह संवैधानिक आदेश संविधान के अनुच्छेद १४ और १५ का विभेदक और उल्लंघन करता है क्योंकि यह हिंदू,

सिख और बौद्ध के अलावा अन्य धर्मों में धर्मांतरित अनुसूचित जाति के खिलाफ भेदभाव करता है। पीआईएल का कहना है कि ईसाई धर्म में धर्मांतरित हुए अनुसूचित जातियों के लोगों की सामाजिक और आर्थिक अक्षमता उनके धर्मांतरण के बाद भी ज्यादातर मामलों में बनी रहती हैं और सिख धर्म और बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म में धर्मांतरित अनुसूचित जातियों के लोगों के बीच भेदभाव नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह सिद्धांत कि ईसाई धर्म जातियों को मान्यता नहीं देता है, ईसाइयों को बाहर करने का एक वैध औचित्य नहीं हो सकता है क्योंकि सिद्धांत रूप में सिख और बौद्ध धर्म भी जातियों को मान्यता नहीं देते हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश १९५० के खंड ३ को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया जाए।

याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद १४ और अनुच्छेद १५ का हवाला दिया गया है। ये अनुच्छेद हैं:

अनुच्छेद १४ – राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद १५ – धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध

१) राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा

२) कोई भी नागरिक, केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। इस संबंध में

३) दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के महलों तक पहुंच ; या

४) कुओं, तालाबों, नहाने के घाटों, सड़कों और सार्वजनिक आश्रय के स्थानों का उपयोग जो पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य निधि से अनुरक्षित हैं या आम

जनता के उपयोग के लिए समर्पित हैं

५) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा

६) इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद २९ के खंड (२) में कुछ भी राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।

नवंबर २०२२ में सरकार ने पीआईएल में की गई मांग का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया। इसमें कहा गया है कि इस्लाम या ईसाई धर्म में कोई पिछड़ापन और अत्याचार नहीं था। यह कहते हुए कि संवैधानिक आदेश (१९५०) किसी भी असंवैधानिकता से ग्रस्त नहीं है, हलफनामे में कहा गया है कि १९५० का आदेश ऐतिहासिक तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित था, जबकि ईसाई या इस्लाम के सदस्यों द्वारा इस तरह के किसी भी उत्पीड़न या पिछड़ेपन का सामना नहीं किया गया था।

हलफनामे में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न तो इस्लाम और न ही ईसाई धर्म जाति व्यवस्था को मान्यता देते हैं, जो हिंदू धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा था। वास्तव में, हलफनामे में आगे कहा गया है कि जातिगत भेदभाव लोगों के इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने का एक प्रमुख कारण था क्योंकि उनका मानना था कि वे अस्पृश्यता की दमनकारी प्रकृति से बाहर आएंगे। संघ सरकार, अपने हलफनामे में, रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों से भी असहमत है, जिसमें कहा गया है कि वे अदूरदर्शी हैं।

बौद्धों के लिए आरक्षण पर हलफनामे में कहा गया है कि लोगों ने सामाजिक–राजनीतिक अनिवार्यताओं के लिए डॉ. अम्बेडकर द्वारा दिए गए आह्वान के जवाब में बौद्ध धर्म को अपनाया, जो इस्लाम या ईसाई धर्म को चुनने वाले लोगों पर लागू नहीं हो सकता है। हलफनामे में आगे कहा गया है कि लोगों ने कुछ

अन्य कारणों से भी इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाया होगा।

इस्लाम और ईसाई धर्म में धर्मांतरित अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण का विरोध करने के अलावा, सरकार ने इस मुद्दे के समाजशास्त्रीय और संवैधानिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस समिति की नियुक्ति अक्टूबर २०२२ में हुई थी। तीन सदस्यीय समिति का नेतृत्व भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन कर रहे हैं जबकि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ. रविंदर कुमार जैन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सदस्य डॉ. सुषमा यादव इस समिति के दो अन्य सदस्य होंगे। समिति को दो साल में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

समिति की शर्तें और संदर्भ (ए) नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देना के मामले की जांच करना, जो ऐतिहासिक रूप से दावा करते हैं कि वे अनुसूचित जाति से संबंधित हैं लेकिन उन धर्म में धर्मांतरित हो गए हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद ३४१ के तहत समय–समय पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों में नहीं किया गया है। (बी) मौजूदा अनुसूचित जातियों की सूची में ऐसे नए व्यक्तियों के जूडाव से मौजूदा अनुसूचित जातियों पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच करना। (सी) अन्य धर्मों में धर्मांतरित हुये अनुसूचित जाति के लोग जिन परिवर्तनों से गुज़रे हैं जैसे की रीति–रिवाजों, परंपराओं, सामाजिक और अन्य स्थिति भेदभाव और अभाव की जांच करना और अनुसूचित जाति का दर्जा देने के सवाल पर इसका निहितार्थ (डी) केंद्र सरकार की सहमति के परामर्श से कोई अन्य संबंधित प्रश्न जो आयोग उचित समझे उनकी जांच करना।

याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, जिसे रंगनाथ मिश्रा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा की गई सिफारिशों पर गहरा भरोसा दिखाया है। भारत में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गौर करने के लिए भारत सरकार द्वारा २९ अक्टूबर २००४ को

इसका गठन किया गया था। हालाँकि, आयोग ने सिफारिशें करते समय कभी भी कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया। इसके अलावा, आयोग मुख्य रूप से धार्मिक अल्पसंख्यक – विशेष रूप से इस्लाम – पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि भाषाई अल्पसंख्यकों के मुद्दे बड़े पैमाने पर उपेक्षित रहते थे। याचिकाकर्ता ने आयोग की सिफारिश का हवाला दिया है, लेकिन अपने तर्क को स्थापित करने के लिए कानूनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। अच्छी तरह से स्थापित कानूनी प्रथा के अनुसार, जब अनुच्छेद १४ के उल्लंघन का दावा किया जाता है तो स्पष्ट और ठोस साक्ष्य के माध्यम से यह स्थापित करने का भार याचिकाकर्ता पर होता है कि राज्य मनमाना भेदभाव का दोषी है। अच्छी तरह से स्थापित कानूनी प्रथा के अनुसार, स्पष्ट और अकाट्य साक्ष्य द्वारा स्थापित करने का भार कि राज्य मनमाने भेदभाव का दोषी है और अनुच्छेद १४ का उल्लंघन करता है, याचिकाकर्ता पर है।

याचिकाकर्ता इस संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। इसके बजाय, वे केवल एक आयोग की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिक और पद्धतिगत अध्ययन की कमी के कारण विश्वसनीयता का अभाव है। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय किसी भी दस्तावेजी शोध और सटीक प्रमाणित जानकारी के अभाव में निर्णय ले, जो यह स्थापित करेगा कि अनुसूचित जाति के सदस्य अपने मूल (हिंदू धर्म) के सामाजिक क्रम में जिन अक्षमताओं और बाधाओं का सामना करते हैं, वे ईसाई या इस्लाम धर्मों के वातावरण में उनकी दमनकारी गंभीरता के साथ बनी रहती हैं।

इसके विपरीत, रेव सैमुअल माटीर, केरल और तमिलनाडु, तत्कालीन त्रावणकोर की रियासत, कोचीन और मद्रास प्रेसीडेंसी के एक ब्रिटिश मिशनरी द्वारा अपने २५ से अधिक वर्षों के भारत प्रवास के दौरान किए गए अध्ययन और क्रमशः १८७० और १८८३ में ''लैंड ऑफ चैरिटी'' और ''नेटिव लाइफ इन त्रावणकोर'' नामक प्रकाशित हुई दो पुस्तकें वर्णन करती हैं कि इन राज्यों कि गुलाम जाति

(वर्तमान अनुसूचित जातियां) जो ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो गईं थी, वे हिंदुत्व में रहे अपने भाइयों की तुलना में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में आ गईं थी।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राष्ट्रपति का आदेश, १९५० असंवैधानिक है क्योंकि यह धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। याचिका में कहा गया है कि ईसाई और इस्लाम धर्म को आदेश से बाहर रखा गया है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने बड़ी आसानी से एक वास्तविकता की उपेक्षा की है कि इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के लिए जगह नहीं है। यह दोनों धर्मों में प्रचलित नहीं है। याचिकाकर्ता इस तथ्य की उपेक्षा करते हैं कि अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव अनुसूचित जाति में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का निर्णायक कारण है।

राष्ट्रपति का आदेश, १९५० ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित था, जिसने स्पष्ट रूप से स्थापित किया था कि ईसाई या इस्लामिक समाज के सदस्यों द्वारा कभी भी इस तरह के पिछड़ेपन या उत्पीड़न का सामना नहीं किया गया था। वास्तविकता यह थी कि अनुसूचित जाति के लोग हिंदू धर्म में प्रचलित दमनकारी व्यवस्था से बाहर आने के लिए इस्लाम या ईसाई जैसे धर्मों में धर्मांतरित होते रहे हैं। इस्लाम और ईसाई धर्म के नेताओं ने हमेशा घोषणा की है कि उनके धर्मों में जातिगत भेदभाव और छुआछूत का कोई स्थान नहीं है। स्वाभाविक रूप से धर्मांतरण के बाद भी जाति से उत्पन्न होने वाले पिछड़ेपन का दावा करना अतार्किक और तर्कहीन है।

एक और महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करना होगा। इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वालों को वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का लाभ मिल रहा है। अदालत के फैसले ने ओबीसी वर्ग के लिए २७ प्रतिशत कोटा तय किया है, जिसमें मुस्लिम और ईसाई धर्म के कुछ समूह शामिल हैं। इसके अतिरिक्त,

ओबीसी वर्ग को अन्य सुविधाएं जैसे पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति, लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास, स्वयंसेवी संगठनों और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा की जाने वाली आय सृजन गतिविधियों की सहायता प्राप्त हो रही है।

एक दर्जन से अधिक राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, दीव/दमन और पुडुचेरी में ईसाई धर्म में धर्मांतरित अनुसूचित जाति के लोगों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति के लोग, जो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों से ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो गए हैं, इस सूची के लाभार्थी हैं।

इसी तरह, इस्लाम में धर्मांतरित कुछ समुदायों को आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में ओबीसी श्रेणी की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है। यह आरक्षण विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त है, जो विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए हैं। ये योजनाएं स्पष्ट रूप से धर्मान्तरित लोगों के लिए लागू होती हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुयायियों को आरक्षण और विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जो विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए हैं।

जनहित याचिका के समर्थकों द्वारा दिया गया एक अन्य प्रमुख तर्क यह है कि अनुसूचित जनजाति, जो ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो गई थी, अनुसूचित जाति आदेश १९५० के दायरे में बनी हुई है, लेकिन अनुसूचित जाति के लोग, जो ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो गए हैं, इसके लाभ से वंचित हैं। इस कारण को भी भेदभावपूर्ण बताया जा रहा है। यह तर्क भी अविवेकी है क्योंकि अनुसूचित जनजाति संविधान अनुसूचित जाति आदेश के दायरे में नहीं आती बल्कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश के दायरे में आती है। यह अनुसूचित

जनजाति के रूप में एक समुदाय के विशिष्टीकरण के लिए अलग मानदंड के अतिरिक्त है। ये मानदंड हैं (ए) आदिम लक्षण (बी) विशिष्ट संस्कृति (सी) भौगोलिक अलगाव, (डी) बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और (ई) पिछड़ापन। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुसूचित जनजातियों के मामले में किस धर्म को माना जा रहा है, विचार का विषय नहीं है। इसके विपरीत, अस्पृश्यता की पारंपरिक प्रथा से उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन, एक जाति को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट करने का मानदंड है।

धर्म के आधार पर भेदभाव के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय से न्यायिक समीक्षा के तहत राष्ट्रपति के आदेश, १९५० की जांच करने का भी आग्रह किया। यह मांग संविधान लागू होने के ७३ साल बाद की गई है। न्यायिक समीक्षा सरकार के विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक अंगों के कार्यों की जांच करने और यह निर्धारित करने के लिए अदालतों की शक्ति है कि क्या ऐसे कार्य संविधान के अनुरूप हैं। असंगत मानी जाने वाली कार्रवाइयों को असंवैधानिक घोषित किया जाता है और इसलिए, यह अशक्त और शून्य है।

याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रपति के आदेश, १९५० की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए न्यायिक हस्तक्षेप के लिए कहा है। लेकिन अनुच्छेद ३४१ (१) स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति को राज्य या संघ के संबंध में राज्य के राज्यपाल के परामर्श से निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। क्षेत्र, या राज्य, जिले या क्षेत्र के एक हिस्से के लिए सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट जाति, मूलवंश या जनजाति या जातियों, मूलवंश या जनजाति के हिस्से या समूह जो संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जाति के संबंध में माने जाएंगे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जैसा भी मामला हो।

अनुच्छेद ३४१ का खंड (२) संसद को कानून द्वारा खंड बी के तहत जारी

अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या बाहर करने का अधिकार देता है। १९६५ में सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की बेंच द्वारा बासवलिंगप्पा बनाम डी मुनिचिनप्पा मामले में इसे बरकरार रखा गया है। मैसूर राज्य में एक जाति के नाम में परिवर्तन पर कानूनी विवाद उत्पन्न हुआ। राज्य सरकार ने एक जाति विशेष का नाम बदलने की तमाम कानूनी कवायद पूरी कर ली थी लेकिन राष्ट्रपति के आदेश में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। भले ही उच्चतम न्यायालय ने सहमति व्यक्त की कि दोनों जातियां समान रहेंगी, उसने यह भी कहा कि अनुच्छेद ३४१ के अंतर्गत एक अधिसूचना को अंतिमता प्रदान की जाती है, सिवाय इसके कि जब संसद द्वारा कानून बदलाव किया जाता है। न्यायालय ने कहा, धारा (१) के तहत जारी अधिसूचना के संबंध में संविधान के कड़े प्रावधान के मद्देनजर, यह किसी भी जाति को साक्ष्य–मौखिक या दस्तावेजी के आधार पर अधिसूचना में शामिल करने के लिए खुला नहीं है, यदि अधिसूचना के संदर्भ में जाति का विशिष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। उच्चतम न्यायालय ने तो यहां तक कह दिया कि उच्च न्यायालय ने गलती की है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है कि वह किसी जाति के नाम को अनुसूची से शामिल या बाहर कर सकते है।

केंद्र सरकार ने भी अपने हलफनामे में यही बात कही है कि न्यायपालिका के पास राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना को लागू करने के अलावा कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि न्यायपालिका एक सीमित उद्देश्य के लिए अनुच्छेद ३४१ (१) और ३४२ (१) के तहत अधिसूचना पर गौर करेगी और इस संबंध में राष्ट्रपति और संसद की शक्ति निर्णायक है।१९६५ में भैया लाल बनाम हरकिशन सिंह मामले में, सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने भी इसी तरह के विचार को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद ३४१ के खंड (१) के तहत जारी अधिसूचना को संसद द्वारा बनाए गए कानून के अलावा किसी भी बाद की अधिसूचना से बदला नहीं जा सकता है। दूसरे शब्दों में, केवल संसद ही कानून अनुसार किसी जाति/जनजाति को उक्त अनुच्छेदों के तहत जारी अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों की सूची में शामिल करने या बाहर करने के लिए सक्षम है।

संविधान सभा में दो अनुच्छेदों– ३४१ और ३४२– के उक्त प्रावधान का समर्थन करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा, ''जैसा कि मैंने कहा था, इन दोनों अनुच्छेदों का उद्देश्य संविधान पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लंबी सूचियों का बोझ डालने की आवश्यकता को समाप्त करना था। अब यह प्रस्तावित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल या शासक के परामर्श से राष्ट्रपति को राजपत्र में एक सामान्य अधिसूचना जारी करने की शक्ति होनी चाहिए जिसमें सभी जातियों और जनजातियों या उनके समूहों का उल्लेख किया गया हो जिन्हे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्दिष्ट किया गया हो। इन विशेषाधिकारों का उद्देश्य, जिन्हें कॉन्डन में परिभाषित किया गया है। इस विषय में केवल यही सीमा लगाई गई है; एक बार राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी कर दी गई है, निस्संदेह, वे प्रत्येक राज्य की सरकार के परामर्श से और उसकी सलाह पर जारी करेंगे। तत्पश्चात, यदि इस प्रकार अधिसूचित सूची से कोई विलोपन किया जाना था या कोई परिवर्धन किया जाना था फिर यह संसद द्वारा किया जाना चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा नहीं। इसका उद्देश्य किसी भी तरह के राजनीतिक कारकों को खत्म करना है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा प्रकाशित कार्यक्रम में किसी भी प्रकार गड़बड़ी उत्पन्न कर सकते हैं।''

डॉ. अम्बेडकर द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण बिना किसी अनिश्चित शब्दों में स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि केवल राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के नामों को शामिल करने या बाहर करने का अधिकार है और कोई भी – न तो कार्यपालिका और न ही न्यायपालिका इसमें संशोधन कर सकती है। सटीक होने के लिए, इस संबंध में शक्ति विधायिका – संसद – के पास होती है क्योंकि राष्ट्रपति भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की सलाह पर निर्णय लेते हैं। इस प्रकार, अनुच्छेद ३४१ और ३४२ के तहत जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश में न्यायपालिका, शामिल किए जाने या हटाने वाली प्रविष्टियों के प्रश्न

से निपटने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकती है और न ही करना चाहिए, विशेष रूप से तब जब उक्त अनुच्छेद के खंड (२) में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अलावा उक्त आदेशों में संशोधन या बदलाव नहीं किया जा सकता है।

श्रेणीबद्ध संवैधानिक प्रावधान के अलावा, एक और कारण है जो संसद को इस मुद्दे पर विचार करने का आधार देता है। न्यायपालिका के विपरीत संसद जमीनी हकीकत जानने और समझने की बेहतर स्थिति में है। जरूरत पड़ने पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए संसद आवश्यक प्रशासनिक तंत्र से भी लैस है। यह मामला न्यायपालिका के लिए नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से अक्षम है और इसमें आवश्यक अध्ययन करने के लिए कोई आधिकारिक तंत्र नहीं है। इस मुद्दे में न्यायिक हस्तक्षेप अनुचित है क्योंकि विधायिका, एक संस्था के रूप में, संरचना और मौलिक प्रकृति के मामले में न्यायपालिका की तुलना में बहुत बड़ी है। विधायिका सावधानीपूर्वक डिज़ाइन की गई अंतर्निर्मित प्रक्रियाओं, अभ्यावेदन और संसाधनों की बहुतायत का उपयोग करती है क्योंकि उनके पास संस्थान के भीतर काम करने वाले लोगों के साथ–साथ कार्यकारी के रूप में बाहर काम करने वाले लोगों की जानकारी, कौशल, विशेषज्ञता और ज्ञान तक पहुंच होती है। कानून और न्यायिक अधिनिर्णय की प्रक्रिया और पद्धति पूरी तरह से अलग हैं। न्यायिक अधिनिर्णय में एक व्यक्तिगत न्यायाधीश या पीठ के ज्ञान और ज्ञान की गहरी समझ के बावजूद व्याख्या के नियमों और मिसाल के कानून को लागू करना शामिल है। इसकी तुलना एक लोकतांत्रिक समाज में विधायक जी द्वारा कानून बनाने से नहीं की जा सकती है, जिनके पास व्यापक और व्यापक विविध राज्य व्यवस्था है।

संविधान में कहा गया है कि विधायिका सर्वोच्च है और कानून के मामलों में उसका निर्णय अंतिम है जब वह विभिन्न क्षेत्रों से निविष्ट के साथ विकल्पों पर विचार करता है, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के रूप में एक जांच के साथ और

अदालतों द्वारा एक और जांच जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करती है। यह न्यायाधीशों के लिए नहीं है कि वे कानून के नए सर्व–सम्मिलित सिद्धांतों को इस तरह से विकसित करने की कोशिश करें जो व्यक्तिगत न्यायाधीशों के रुख और राय को दर्शाता है जब समाज/विधायक समग्र रूप से अस्पष्ट हैं और प्रासंगिक मुद्दों पर काफी हद तक विभाजित हैं। सही निर्णय सही निकाय द्वारा लिया जाना चाहिए। अदालत का कार्य यह देखना है कि वैध अधिकार का दुरुपयोग न हो, लेकिन उस प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य को स्वयं के लिए उपयुक्त नहीं किया जाए। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि वैधानिक अधिकारों के साथ निवेशित एक सार्वजनिक निकाय को अपने अधिकार से अधिक अधिकार का प्रयोग या इसका दुरुपयोग नहीं करने का ध्यान रखना चाहिए। आरक्षण जाति को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है न कि उसे कायम रखने के लिए। आरक्षण का उपयोग सीमित अर्थ में करना होगा अन्यथा यह देश में जातिवाद को बढ़ावा देगा।

आरक्षण एक विशेष औचित्य द्वारा लिखा गया है। अनुच्छेद १६(१) में समानता व्यक्ति–विशिष्ट है जबकि अनुच्छेद १६(४) और अनुच्छेद १६(४–ए) में आरक्षण समर्थ बनाता है। हालांकि, राज्य का विवेकाधिकार सार्वजनिक रोजगार में पिछड़ेपन के अस्तित्व और 'प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता' के अधीन है। पिछड़ापन वस्तुनिष्ठ कारकों पर आधारित होना चाहिए जबकि अपर्याप्तता तथ्यात्मक रूप से मौजूद होनी चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि राष्ट्रपति का आदेश, १९५० अनुच्छेद १४ का उल्लंघन करता है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी कानूनों को प्रकृति में सामान्य और आवेदन में सार्वभौमिक होना चाहिए और यह कि विधायिका के पास कानून के प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों को अलग करने और वर्गीकृत करने की शक्ति नहीं है। अनुच्छेद १४ की अपेक्षा यह है कि कोई भी वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए और बोधगम्यता अंतर पर आधारित होना चाहिए।

महत्वपूर्ण न्यायालयीन फैसलें

वर्तमान जनहित याचिका ने कई संवैधानिक मुद्दों को उठाया है जिन पर न्यायपालिका ने निर्णय दिए हैं और अध्याय को बंद कर दिया है। जनहित याचिका में मुख्य रूप से कुछ संवैधानिक मुद्दे शामिल हैं जिनमें धार्मिक भेदभाव, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, इस्लाम और ईसाई धर्म में जाति का अस्तित्व और जाति का निर्धारण शामिल हैं। निम्नलिखित कुछ प्रमुख न्यायालयीन फैसलें हैं।

जाति और अब्राहिम धर्म

१) सूसई बनाम भारत संघ – एक ऐतिहासिक फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदू अनुसूचित जाति के रूप में दावा करने के हकदार नहीं हैं और वह जाति धर्मांतरण के बाद जारी नहीं रखी जा सकती है। ३० सितंबर, १९८५ को न्यायमूर्ति आर एस पाठक द्वारा फैसला सुनाया गया था। इस मामले में एक मोची शामिल था, जिसने ईसाई धर्म को अपना लिया था। उसने एक कल्याणकारी योजना के लिए आवेदन किया, जो केवल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए थी। उसने दावा किया कि वह उस जाति का ही सदस्य था, जिससे वह धर्मांतरण से पहले संबंधित था। हालाँकि, उसे इस योजना के लाभ से इस आधार पर वंचित कर दिया गया था कि उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, जो जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देता है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रपति के आदेश में विशेष रूप से हिंदू और सिख समुदाय के लोगों का उल्लेख है, जिन्हें जातिगत भेदभाव से सुरक्षा की जरूरत है।

उच्चतम न्यायालय आदेश में कहता है, ''संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान केवल उन जातियों के

सदस्यों के लिए लागू होगा जिन्हे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, १९५० में सूचीबद्ध किया गया है, जो हिंदू या सिख धर्म को मानते हैं। यदि कोई ईसाई उन जातियों में से किसी एक से संबंधित है, तो उसे अनुच्छेद ३ के कारण अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में नहीं माना जाएगा और, इसलिए अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के लाभ के हकदार नहीं होंगे।''

२) कैलाश सोनकर बनाम श्रीमती माया देवी – इस मामले में पुनःधर्म पंरिवर्तन का एक दिलचस्प पहलू है। माया देवी को ईसाई धर्म में धर्मांतरित किया गया और हिंदू धर्म में पुनःधर्मांतरित किया गया। विचाराधीन मुद्दा यह था कि क्या उसे धर्मांतरण से पहले की जाति का सदस्य माना जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने १६ दिसंबर, १९८३ को फैसला सुनाया था। मामले के अनुसार, माया देवी ने मध्य प्रदेश के एक निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। उसने खुद को कटिया जाति का सदस्य बताया, जो अनुसूचित जाति की सूची में है। उनके नामांकन पत्र को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि माया देवी ईसाई थी और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकती थी। उनके चुनाव को कैलाश सोनकर ने चुनौती दी थी। माया देवी के दो तर्क थे – उनके माता–पिता कभी भी ईसाई नहीं थे और उन्होंने कटिया समुदाय के जय प्रकाश सलवार से विवाह किया था। अपीलकर्ता द्वारा उसके तर्क का विरोध किया गया और कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसमें दिखाया गया कि वह ईसाई समुदाय से संबंधित थी।

अदालत इस निष्कर्ष पे पंहुची कि, (ए) माया देवी का जन्म ईसाई माता–पिता के घर में हुआ था और स्कूल और अन्य शैक्षिक संस्थानों में ईसाई के रूप में जानी जाती थीं। (बी) शुद्धिकरण समारोह आयोजित करके वह हिंदू धर्म में पुनःधर्मांतरित हुई और कटिया जाति के जय प्रकाश से शादी की। (सी) कटिया समुदाय के सदस्यों द्वारा उसे स्वीकार किया गया और उसका स्वागत

किया गया। (डी) यह दिखाने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि ईसाई धर्म के अंतर्गत कोई अवरोध था जो उसे खुद को हिंदू धर्म में पुनःधर्मांतरित होने से रोक रहा था। माया देवी के चुनाव को चुनौती देने वाली अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने, हालांकि, फैसले में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। इसमें कहा गया कि, ''जब तक नया धर्म जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है और धर्म परिवर्तन करने वाले को अपनी मूल जाति और परिवार के कानूनों को बनाए रखने की अनुमति नहीं देता है, तब तक धर्मान्तरित (कनवर्टी) अपनी जाति खो देता है। धर्मांतरण के दौरान मूल जाति पर ग्रहण लग जाता है। मूल धर्म में पुन:धर्म परिवर्तन होने पर ग्रहण समाप्त हो जाता है।''

३) मद्रास उच्च न्यायालय – ३ दिसंबर, २०२२ को, मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक व्यक्ति दूसरे धर्म में धर्मांतरण के बाद अपनी जाति से जूड़ा नहीं रह सकता है। यह टिप्पणी एक व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए आई, जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया था और धर्मांतरण से पहले अपनी जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग आरक्षण की मांग की थी। यह फैसला न्यायाधीश जी आर स्वामीनाथन ने दिया।

याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टीएनपीएससी) द्वारा उसे पिछड़ा वर्ग के बजाय संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा– II (ग्रुप– II सेवाएं) में 'सामान्य' श्रेणी में मानने की कार्रवाई को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि जब एक बार एक व्यक्ति, जो एक हिंदू पैदा हुआ, दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो जाता है जो जाति व्यवस्था का पालन नहीं करता है या उसे मान्यता नहीं देता है, तब धर्मांतरित व्यक्ति का उस जाति से संबंध नहीं रहता जिसमें उसका जन्म हुआ था।

न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने कैलाश सोनकर बनाम माया देवी मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि एक हिंदू की जाति उसके जन्म से निर्धारित होती है। इसलिए, यदि कोई हिंदू ईसाई धर्म या इस्लाम में धर्मांतरित हो जाता है, या कोई अन्य धर्म में जो जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देता है, तो जाति से उसका संबंध समाप्त हो जाता है। मूल धर्म में पुनःधर्मांतरित होने पर, स्वतः ही व्यक्ति का उस जाति से संबंध स्थापित हो जाएगा जिसमें उसका मूल रूप से जन्म हुआ था।

इसलिए टीएनपीएससी के फैसले को अदालत ने बरकरार रखा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म का पालन करने के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहा था। लेकिन न्यायालय का फैसला याचिकाकर्ता के खिलाफ गया।

४) जी माइकल बनाम एस वेंकटेश्वर – १९५१ में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक याचिका को रद्द कर दिया, जिसमें अनुसूचित जाति सूची के प्रावधान को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति राजमन्नार वी अय्यर ने फैसले में विशेष रूप से कहा कि ''एक धर्मांतरित व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती।'' जी माइकल पराईयन समुदाय के सदस्य थे लेकिन ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो गए और अध्यक्षीय आदेश के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए। न्यायालय के अनुसार, ''यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ने मनमाने ढंग से किसी ऐसे हिस्से या समूह को निर्दिष्ट नहीं किया है जिसका कोई स्वतंत्र ध्येय अस्तित्व नहीं है। मेरी राय में, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश वैध है और राष्ट्रपति की शक्तियों के अनुसार है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।''

५) केरल में ए राजा का मामला – दिसंबर २०२२ में केरल उच्च न्यायालय ने भी एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इसने इडुक्की जिले में आरक्षित विधानसभा

क्षेत्र देवीकुलम से सीपीआई (एम) के ए राजा के चुनाव को निरर्थक घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति पी सोमराजन ने फैसला सुनाया कि राजा केरल राज्य के अंतर्गत 'हिंदू परयन' के सदस्य नहीं हैं और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा में सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं हैं।

ए राजा के खिलाफ याचिका यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के पराजित डी कुमार ने दायर की थी। अदालत ने परिवार, बपतिस्मा, विवाह और दफन पंजिका से संबंधित विवरणों की जांच की और पाया कि राजा वास्तव में नामांकन पत्र जमा करने के दौरान ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे और बहुत पहले ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो गए थे। न्यायालय ने कहा कि धर्मांतरण के बाद राजा हिंदू धर्म का सदस्य होने का दावा नहीं कर सकता था। उस आधार पर भी निर्वाचन अधिकारी को उनका नामांकन खारिज कर देना चाहिए था। संक्षेप में, दोनों आधारों पर, यह स्पष्ट है कि राजा केरल राज्य के अंतर्गत 'हिंदू परयन' के सदस्य नहीं हैं और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर चुने जाने के योग्य नहीं हैं।

राजा के खिलाफ यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपना नामांकन पत्र यह दावा करते हुए दाखिल किया कि वह 'हिंदू परयन' से संबंधित हैं। देवीकुलम तहसीलदार द्वारा जारी किया गया और उनके नामांकन पत्र के साथ जमा किया गया जाति प्रमाण पत्र गलत था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसका प्रतिद्वंद्वी अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि जो लोग केरल में हिंदुओं के अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, उन्हें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए केरल राज्य में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। ईसाई धर्म से संबंधित व्यक्ति या धर्मांतरित ईसाई इसके लिए योग्य नहीं हो सकता। वास्तव में, उनका बपतिस्मा सीएसआई चर्च, कुंदरा प्रभाग में हुआ था। याचिकाकर्ता का आरोप था कि बिना उचित पूछताछ के तहसीलदार ने प्रमाण पत्र जारी किया।

हालांकि, राजा ने कहा कि तहसीलदार ने सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया। इसलिए उनके नामांकन पत्र की स्वीकृति पूरी तरह से वैध थी। हालाँकि, ए राजा द्वारा की गई सभी दलीलों को न्यायालय ने ठुकरा दिया था।

६) न्यायाधीश अरुण मिश्रा और एम एम शांतनगौदर की उच्चतम न्यायालय बेंच ने जनवरी २०१८ में कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि जाति जन्म से निर्धारित होती है और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ शादी करके जाति को नहीं बदला जा सकता है। इस मामले में उच्च जाति की एक महिला शामिल थी, जिसने अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) वर्ग के एक व्यक्ति से शादी की थी। महिला को अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) वर्ग में नौकरी मिली थी।

७) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने समरूप निर्णय दिया कि जाति जन्म से निर्धारित होती है। यह उच्च जाति की एक महिला का मामला था, जिसने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है क्योंकि उसकी जाति जन्म से अलग थी। फैसला न्यायाधीश कृष्णा दीक्षित ने दिया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में भी यही फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि किसी व्यक्ति की जाति का दर्जा जन्म से निर्धारित होती है न कि विवाह से।

सवाल यह उठता है – अगर जाति जन्म से निर्धारित होती है और यहां तक कि शादी भी इसे बदल नहीं सकती है, तो कैसे धर्मान्तरित लोग जाति–आधारित लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि उनके धर्म जाति व्यवस्था को मंजूरी नहीं देते हैं? इसी तरह के निर्णय कई मामलों में दिए गए हैं जिनमें न्यायालयों ने लगातार निम्नलिखित विचारों को बरकरार रखा है ए) जाति केवल हिंदू समुदाय तक ही

सीमित है। बी) अन्य धर्मों में जाति का कोई स्थान नहीं है। सी) हिंदू अनुसूचित जाति के लोग, जो अन्य धर्मों में धर्मांतरित हो, आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते। डी) अनुसूचित जाति के लोग, जो अन्य धर्मों में धर्मांतरित हो गए थे, लेकिन हिंदू धर्म में पुनःधर्मांतरित हो गए हो, वे आरक्षण का लाभ उठा सकता है।

भारत के राष्ट्रपति के अधिकार

उच्चतम न्यायालय के पहले के सभी निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल राष्ट्रपति ही कोई संशोधन करने के लिए अधिकृत हैं। न्यायपालिका अगर इस मामले में दखल देगी तो वह अपनी संवैधानिक मर्यादाओं को पार कर जाएगी। यह तर्क अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी संशोधन पर भी लागू होता है।

यह स्थिति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा २००६ में माना आदिम जमात बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में व्यक्त की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा, यह अब कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि वैध रूप से संसद के अलावा कोई भी प्राधिकरण राष्ट्रपति के आदेशों में संशोधन नहीं कर सकता है। न तो राज्य सरकारें और न ही न्यायालय और न ही न्यायाधिकरण और न ही कोई प्राधिकरण जांच करने के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण कर सकता है और यह घोषित करने के लिए सबूत ले सकता है कि एक जाति या जनजाति या किसी जाति या जनजाति का हिस्सा या एक समूह राष्ट्रपति के आदेशों में एक प्रविष्टि या अन्य में शामिल है, हालांकि वे स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से शामिल नहीं हैं। एक न्यायालय उक्त राष्ट्रपति के आदेशों को बहुत अच्छे कारण से बदल या संशोधित नहीं कर सकता है क्योंकि अनुच्छेद ३४१ और ३४२ के अर्थ, प्रकरण और दायरे में ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं है।

एस. स्वविगराडोस बनाम भारतीय खाद्य निगम मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा, अनुच्छेद ३४१(१) भारत के राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राज्य, जिले या क्षेत्र के हिस्से के संबंध में सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों या जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति माना जाएगा, जैसी स्थिति हो। खंड (२) अनुच्छेद ३४१ संसद को कानून द्वारा धारा (१) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में किसी भी जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी भी जाति, मूलवंश या जनजाति के अंतर्गत या समूह को शामिल करने या बाहर करने का अधिकार देता है, लेकिन पूर्वोक्त के अलावा उक्त खंड के तहत जारी अधिसूचना किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा धर्मांतरित नहीं की जाएगी। दूसरे शब्दों में, संवैधानिक जनादेश यह है कि राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति, एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जाति, मूलवंश या जनजाति या भागों या जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के अंतर्गत समूह को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत है, जो संविधान के उद्देश्यों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति माने जाएंगे। इसलिए, न्यायालयों के पास राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना को प्रभावी करने के अलावा कोई शक्ति नहीं है। यह स्थापित कानून है कि न्यायालय एक सीमित उद्देश्य के लिए सार्वजनिक अधिसूचना पर गौर करेगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९७६ के तहत राष्ट्रपति और संसद के अधिनियम द्वारा जारी अधिसूचना और उससे जुड़ी अनुसूचियों को यह पता लगाने के उद्देश्य से देखा जा सकता है कि क्या जाति, मूलवंश या जनजाति (एसआईसी या) संविधान के प्रयोजनों के लिए जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या समूह अनुसूचित जाति होंगे।

संशोधन अधिनियम १९७६ के तहत, संसद ने फिर से संविधान में संलग्न अनुसूचियों में शामिल या बहिष्कृत किया है, जो अब निर्णायक हैं। अनुसूची १ अनुसूचित जातियों से संबंधित है और अनुसूची २ अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के तहत ईसाई अनुसूचित जाति नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कई मौकों पर यह माना था कि केवल राष्ट्रपति, संसद द्वारा कानून पारित करने के बाद, अनुसूचित जातियों की सूची में कोई बदलाव करने के लिए अधिकृत हैं।

यह कहाँ ले जाएगा?

यदि इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण दिया जाता है तो निस्संदेह भारत को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसे 'तुष्टिकरण की नीति' की निरंतरता के रूप में देखा जाना लाजिमी है। वस्तुत: मांग सत्तर वर्षों की तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है, जो समानता के सिद्धांत की घोर अवहेलना है। यह विडंबना है कि याचिकाकर्ता आरक्षण के मामले में धार्मिक भेदभाव की ओर इशारा करते हैं, लेकिन आसानी से अपने अल्पसंख्यक दर्जे के लाभों की उपेक्षा करना चुनते हैं, जो कि धर्म पर आधारित है।

दिलचस्प बात यह है कि 'अल्पसंख्यक' शब्द को भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन यह केवल कुछ लेखों में दिखाई देता है। अंततः 'अल्पसंख्यक' शब्द इस्लाम और ईसाई धर्म का पर्यायवाची बन गया है। अल्पसंख्यक शब्द अनुच्छेद २९ में प्रकट होता है, जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। यह विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति की बात करता है न कि केवल धर्म की। इसी प्रकार, अनुच्छेद ३० 'शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार' से संबंधित है। फिर से, लेख भाषा के बारे में भी बात करता है न कि केवल धर्म के बारे में। अनुच्छेद ३५० (ए) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति के बारे में कहता है।

वर्तमान में, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, १९९२ की धारा २ (सी) के तहत अधिसूचित समुदायों को ही अल्पसंख्यक माना जाता है। एनसीएम अधिनियम की धारा २ (सी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र ने २३ अक्टूबर, १९९३ को पांच समूहों – मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी – को 'अल्पसंख्यक' समुदायों के रूप में

अधिसूचित किया। जैन धर्मियों को जनवरी २०१४ में सूची में जोड़ा गया था। वास्तविकता यह है कि अल्पसंख्यक शब्द इस्लाम और ईसाई धर्म का पर्याय बन गया है।

दोहरा लाभ

भले ही संविधान में विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख नहीं है, लेकिन इस्लाम और ईसाई धर्म पर विशेष रूप से नजर रखते हुए कई नीतियां बनाई जा रही हैं। कागज पर, सभी नीतियां अल्पसंख्यकों के बारे में बोलती हैं लेकिन उनका लाभ दो धर्मों – इस्लाम और ईसाई के सदस्यों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। २०२२ में अकेले केंद्र सरकार के पास १४ विभिन्न अलग–अलग योजनाएं थीं, जो विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई थीं। इनमें से कई योजनाएं शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा/छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास, शैक्षिक ऋण पर सब्सिडी, कमाने और सीखने और कौशल विकास से संबंधित थीं। शिक्षा और पेशा इन योजनाओं के केंद्र बिंदु पर हैं।

इसके अलावा सभी राज्यों की अपनी अलग नीतियां और योजनाएं हैं, जो अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई हैं। जमीनी स्तर पर इस्लाम और ईसाई धर्म के मानने वालों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, वे अन्य सभी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं, जो गैर–अल्पसंख्यक लोगों के लिए लागू हैं। उदाहरण के लिए, इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुयायी – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) जैसी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, आदि। यदि विभिन्न राज्य सरकारों की योजनाओं को ध्यान में रखा जाए तो इस सूची का कोई

अंत नहीं होगा।

केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुयायियों को आरक्षण श्रेणी का लाभ मिल रहा है। अनुसूचित जाति के लोगों का धर्मांतरण इन योजनाओं का लाभ पाने में बाधक नहीं है। इस प्रकार, धर्मांतरित अनुसूचित जाति के लोगों को उनके अल्पसंख्यक दर्जे के कारण दोहरा लाभ मिलता रहेगा।

एक और बड़ी सच्चाई भी अनदेखी की जाती है। ईसाई और मुसलमानों को पहले से ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है क्योंकि दोनों धर्मों के कई समूह ओबीसी की श्रेणी में आते हैं। मंडल आयोग ने ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के लिए मुसलमानों के ८२ उपसमूहों की पहचान की है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक करीब ४१ फीसदी मुस्लिम आबादी ओबीसी श्रेणी में आती है और ओबीसी आरक्षण का लाभ उठाती है। देश में कुल ओबीसी आबादी का १५.७ फीसदी ओबीसी मुसलमान हैं। इसी तरह, ईसाई धर्म के कई उपसमूह ओबीसी श्रेणी में शामिल हैं। यह प्रवृत्ति दक्षिणी और उत्तर–पूर्व राज्यों में दृढ़ता से देखी जाती है।

मौजूदा स्थिति संदेह पैदा करती है कि क्या मुस्लिम और ईसाई आरक्षण के नाम पर अल्पसंख्यक का मुखौटा पहनकर तमाम मौकों को हड़पना चाहते हैं। यह परिदृश्य अस्वीकार्य है क्योंकि यह मौलिक रूप से अनुच्छेद १४ का खंडन करता है – जो धार्मिक आधार पर भेदभाव के बारे में कहता है। सवाल उठता है – किस संवैधानिक प्रावधान के तहत धर्मांतरित अनुसूचित जाति के लोगों को अल्पसंख्यक के एक बैनर से दोहरा लाभ मिलेगा? क्या यह संवैधानिक नैतिकता का सम्मान करता है? क्या धर्मांतरित अनुसूचित जाति के लोग एक और लाभ पाने के लिए पहला टैग छोड़ने को तैयार हैं? यदि धर्मांतरित अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण दिया जाता है तो देश को गंभीर सामाजिक अशांति का सामना करना पड़ेगा क्योंकि लोग पहले से ही तुष्टीकरण

की राजनीति से नाराज हैं।

हिंदुओं के अधिकार छीन रहे हैं

अनुसूचित जाति के लोग, जो इस्लाम या ईसाई धर्म में धर्मांतरित नहीं हुए हैं, धर्मांतरितों के लिए आरक्षण बढ़ाए जाने के मामले में सबसे पहले शिकार होंगे। उनकी संभावनाएं खतरे में पड़ जाएंगी क्योंकि मुसलमान और ईसाई बड़े पैमाने पर आरक्षण के लाभ उठायेंगे। ऐसा तब होगा जब आरक्षण कोटे में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। यह सामाजिक अशांति पैदा करने के लिए बाध्य है क्योंकि धर्मांतरितों के लिए आरक्षण का विषय कभी भी एजेंडे में नहीं था। किसी ने भी ऐसे परिदृश्य की कल्पना नहीं की थी जिसमें धर्मांतरित लोगों को आरक्षण मिलेगा।

आरक्षण के विस्तार से निश्चित रूप से सामाजिक तनाव पैदा होगा। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि निकट भविष्य में दो अब्राहमिक धर्म आरक्षण के सभी लाभों को हड़प लेंगे। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा प्रकाशित आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, २०११ की जनगणना में भारत की जनसंख्या १२१.०९ करोड़ थी। हिंदुओं की जनसंख्या ९६.६३ करोड़ (७९.८ प्रतिशत) थी जबकि मुसलमानों की संख्या १७.२२ करोड़ (१४.२ प्रतिशत) थी। २०११ की जनगणना रिपोर्ट कहती है कि ईसाई आबादी २.७८ करोड़ (२.३ प्रतिशत) थी। सिखों की जनसंख्या २.०८ करोड़ (१.७ प्रतिशत), बौद्ध जनसंख्या ०.८४ करोड़ (०.७ प्रतिशत), जैन जनसंख्या ०.४५ करोड़ (०.४ प्रतिशत) है। अन्य धर्मों की जनसंख्या ०.७९ करोड़ (०.७ प्रतिशत) थी।

२०११ की जनगणना एक चौंकाने वाली प्रवृत्ति के साथ सामने आई, जिसके अनुसार हिंदुओं, सिखों, बौद्धों (अखिल भारतीय धर्मों की उत्पत्ति) की जनसंख्या में गिरावट आई थी। ईसाई आबादी स्थिर थी। जनसंख्या में तीव्र

वृद्धि केवल मुस्लिम धर्म में ही नोट की गई थी। हिंदू आबादी में ०.७ प्रतिशत की गिरावट आई जबकि सिख आबादी में ०.२ प्रतिशत की कमी आई। इसी तरह बौद्ध आबादी में ०.१ फीसदी की गिरावट आई है। जैन और ईसाईयों ने कोई गिरावट दर्ज नहीं की और स्थिर थे। जनसंख्या में वृद्धि केवल मुस्लिम धर्म में ही देखी गई। इसकी वृद्धि ०.८ प्रतिशत थी। हिंदुओं में जनसंख्या की वृद्धि दर १६.८ प्रतिशत थी जबकि ईसाइयों में यह १५.५ प्रतिशत थी। बौद्धों और जैन धर्मियों के बीच विकास दर क्रमशः ८.१ प्रतिशत और ५.४ प्रतिशत थी। जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, मुसलमानों की वृद्धि दर उच्चतम – २४.६ प्रतिशत थी।

आजादी के बाद से मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है। १९५१ में की गई पहली जनगणना में, मुस्लिम आबादी ९.८ प्रतिशत थी और २०११ में यह बढ़कर १४.२ प्रतिशत हो गई। आंकड़ों से पता चलता है कि हिंदू आबादी घट रही थी, ईसाई स्थिर थे। मुस्लिम आबादी अभूतपूर्व दर से बढ़ रही थी।

प्यू रिसर्च सेंटर ने २०५० में भारतीय जनसंख्या के प्रक्षेपण पर एक अध्ययन किया है। रिपोर्ट फरवरी २०२१ में प्रकाशित हुई थी। प्यू रिपोर्ट के अनुसार, २०५० में मुस्लिम आबादी ७६ प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ ३११ मिलियन होगी। ३३ प्रतिशत वृद्धि दर के साथ हिंदू आबादी १.३ अरब होगी। दूसरे शब्दों में, हिंदू २०५० में भारतीय आबादी का ७७ प्रतिशत हिस्सा होंगे जबकि मुस्लिम आबादी १८ प्रतिशत होगी। दिलचस्प बात यह है कि ईसाई आबादी दो प्रतिशत के साथ स्थिर बनी रहेगी। प्यू रिसर्च सेंटर ने भविष्यवाणी की है कि अन्य धर्मों की आबादी नगण्य होगी। दूसरे शब्दों में, भारत में केवल हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म होंगे, जबकि सिख, बौद्ध और जैन सूक्ष्म–अल्पसंख्यक में बदल जाएंगे।

इन सभी आंकड़ों को मौजूदा आंकड़ों की पृष्ठभूमि में देखना होगा। जबकि जनगणना इस्लाम और ईसाई जैसे धर्मों में जाति पर विचार नहीं करती है,

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण इस संबंध में कुछ संकेतक दिखाता है। २०१९–२०२१ में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया है कि ईसाइयों में अनुसूचित जाति (एससी) की आबादी ६७,४७,६४१ थी जबकि ९३,१८,१७० अनुसूचित जनजातियों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। एनएफएचएस की रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम बनने वाले अनुसूचित जाति (एससी) की संख्या लगभग ४२,९२,३९४ है जबकि एसटी वर्ग के ४२,९२,३४९ लोग मुस्लिम थे। दूसरे शब्दों में, २,४६,५०,५५४ अनुसूचित जाति के लोग, जो या तो इस्लाम या ईसाई धर्म से संबंधित हैं, आरक्षण के लाभों का अतिक्रमण करेंगे, जो वर्तमान में अनुसूचित जाति द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं, जो अभी भी हिंदू/बौद्ध/सिख बने हुए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का १६.६ प्रतिशत होने का अनुमान है। २० करोड़ से ज्यादा लोग इस कैटेगरी के हैं। मुस्लिम (१४.२ प्रतिशत) और ईसाई (२.७८ प्रतिशत) मिलकर भारत की जनसंख्या का १६.९८ प्रतिशत हैं। मुसलमानों और ईसाइयों का संयोजन थोड़ा अधिक है और वे अनुसूचित जाति के साथ आरक्षण का लाभ साझा करेंगे, जिन्होंने धर्मांतरण का विकल्प नहीं चुना। यह स्थिति जटिल होने जा रही है, सामाजिक समस्याओं को आमंत्रित कर रही है, क्योंकि आरक्षण कोटा में वृद्धि की संभावना बहुत कमजोर है।

धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहन

भारतीय संविधान का अनुच्छेद २५ अंतरात्मा की स्वतंत्रता के अधिकार और सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। हालांकि, राज्यों के पास अवैध रूपांतरण को परिभाषित करने और अनुच्छेद २५ के दुरुपयोग को रोकने के लिए अलग–अलग कानून हैं। अवैध धर्मांतरण के लिए आम तौर पर स्वीकृत आधार हैं १) लालच २) बल का प्रयोग ३) जबरदस्ती ४)

धोखाधड़ी के तरीके। यहां तक कि सामूहिक धर्मांतरण को भी अवैध माना जाता है। लालच के कारण धर्मांतरण के मामले में, कानून के तहत उपहार, संतुष्टि, आसान पैसा, भौतिक लाभ या नकद, रोजगार, मुफ्त शिक्षा और बेहतर जीवन शैली जैसे कारकों पर विचार किया जाता है।

धर्मांतरण विरोधी कानून आंशिक रूप से सफल रहा है क्योंकि इस तरह के कानून के अभाव में भारत की जनसांख्यिकी में भारी बदलाव आया होगा। इसे सख्ती से लागू किया गया होता तो यह और अधिक सफल होता। आरक्षण ईसाई मिशनरियों और मुस्लिम मौलवियों के लिए अपने धर्म का प्रसार करने में एक बड़ी बाधा है। अब्राहीम धर्म के प्रचारकों द्वारा तमाम तरह के प्रलोभन, बलप्रयोग, कपटपूर्ण तरीके और भ्रामक जानकारी देने के बावजूद लाखों अनुसूचित जाति के लोग इस डर से धर्मांतरित नहीं होते कि धर्मांतरण की स्थिति में उन्हें आरक्षण छोड़ना पड़ेगा। यदि धर्मान्तरितों के लिए आरक्षण बढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से धर्मांतरण की गति अधिक होगी।

सवाल उठता है – क्या धर्मांतरितों के लिए आरक्षण को 'कानूनी प्रलोभन' माना जा सकता है। आरक्षण, धन और बाहुबल के साथ मिलकर निश्चित रूप से धर्मांतरण के कारण भारत की जनसांख्यिकी को बदल देगा। यह एक बड़ी समस्या होगी क्योंकि बांग्लादेश से बढ़ती घुसपैठ और हिंदुओं के धर्मांतरण के कारण हिंदुओं की आबादी पहले से ही घट रही है। धर्मांतरण पहले से ही देश के कई हिस्सों में जनसंख्या में असंतुलन का कारण बन रहा है। यह पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर पूर्व राज्यों जैसे राज्यों में देखा जाता है। धर्मांतरण ने पहले ही देश के कुछ हिस्सों में जनसांख्यिकी को बदल दिया है। इस पृष्ठभूमि में, धर्मान्तरित लोगों के लिए आरक्षण धर्मांतरण को और तेज करेगा और राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा पैदा करेगा।

जबरन धर्मांतरण कोई अफवाह नहीं बल्कि एक गंभीर सच्चाई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी जबरन धर्मांतरण पर चिंता जताई है। जस्टिस एम आर शाह

और हिमा कोहली की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नवंबर २०२२ में कहा, जबरन धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा कर सकता है और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। उसने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी जानना चाहा।

अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान, एससी बेंच ने चेतावनी दी कि अगर धोखे, लालच और धमकी के माध्यम से धर्मांतरण को रोका नहीं गया तो एक कठिन स्थिति सामने आएगी। यह बेहतर है कि केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे और इस बात पर काउंटर फाइल करे कि इस तरह के जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं, शायद बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से।

सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में जबरन धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर हो रहा है और लोगों को पता नहीं है कि यह आपराधिक अपराध का विषय है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता हो सकती है लेकिन जबरन धर्मांतरण से धर्म की स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। स्थिति की गंभीरता को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से समझा जा सकता है क्योंकि वह 'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा' शब्दों का उपयोग करने से नहीं हिचकिचाया।

धर्मांतरितों के लिए आरक्षण का विस्तार पहले से ही अस्थिर स्थिति में ईंधन जोड़ देगा क्योंकि आरक्षण का उपयोग अनुसूचित जातियों के लोगों को धर्मांतरण के लिए लुभाने के लिए किया जाएगा। ऐतिहासिक तथ्य को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता। इतिहास बताता है कि दो अब्राहीम धर्मों में धर्मांतरण ने अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा दिया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र की भौगोलिक अखंडता को खतरा पैदा हो गया। इसे कुछ सीमावर्ती राज्यों में आसानी से अनुभव किया जा सकता है। अब्राहीम धर्मों में धर्मांतरण के बाद

कई धर्मान्तरित बिना सोचे समझे या जानबूझकर अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बन जाते हैं, जिसका उद्देश्य धर्मांतरण के माध्यम से भारत की प्रकृति और आत्मा को बदलना है।

ईसाई मिशनरियों की भूमिका हमेशा से ही संदेहास्पद और लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। वे अनुसूचित जाति के लोगों को यह वादा करके फुसलाते रहे हैं कि अगर वे धर्म परिवर्तन करते हैं तो उन्हें जाति–आधारित कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिशनरी अनुसूचित जाति के लोगों को बताते रहे हैं कि ईसाई धर्म में जाति का कोई स्थान नहीं है। हालाँकि, वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं क्योंकि ईसाई निकाय सार्वजनिक रूप से इसके विपरीत कुछ कह रहे हैं।

पोप जॉन पॉल द्वितीय की भारत यात्रा के दौरान विरोधाभास सामने आया। कैथोलिक ईसाइयों के सर्वोच्च धार्मिक प्रमुख पोप ११ नवंबर, २००३ को तमिलनाडु में थे। लोगों को अपने संबोधन में, पोप ने बड़े पैमाने पर जाति–आधारित भेदभाव का उल्लेख किया, जो धर्मांतरित ईसाइयों द्वारा अनुभव किया जा रहा था।

अप्रैल १९८८ में, भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन ने अपनी द्विवार्षिक बैठक में एक बयान जारी किया, हम दुख की बात जानते हैं कि ईसाई भी बड़े समाज के कई नकारात्मक पहलुओं को बनाए रखते हैं, जिसका वे एक हिस्सा हैं। चर्च में शामिल होने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को समानता का समुदाय और जातिगत उत्पीड़न से मुक्ति मिलनी चाहिए थी। लेकिन उनमें से बहुत से लोग दो बार भेदभाव महसूस करते हैं । अनुसूचित जाति मूल के अधिकांश ईसाई अभी भी आर्थिक अवसरों, पर्याप्त शैक्षिक सुविधाओं तक पहुंच, नेतृत्व की भूमिका और निर्णय लेने में भागीदारी से वंचित हैं।

कैथोलिक बिशप्स कांफ्रेंस ऑफ इंडिया (सीबीसीआई) ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को जाति–आधारित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कहा गया है कि अनुसूचित जाति ईसाइयों को चर्च के भीतर और बाहर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सीबीसीआई की वेबसाइट कहती है, २४ मिलियन ईसाइयों की आबादी में अनुसूचित जाति वर्ग की संख्या लगभग १६ मिलियन है। इनमें से अधिकांश दलित ईसाई आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी राज्यों में हैं। वेबसाइट का कहना है कि दलित ईसाइयों को तीन बार भेदभाव का सामना करना पड़ता है – चर्च के भीतर, चर्च के बाहर और सरकार द्वारा।

सीबीसीआई ने इस उद्देश्य के लिए आठ सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा भी की है। वे हैं: i) दलित ईसाइयों के समान अधिकारों के लिए लॉबिंग, वकालत और संघर्ष, ii) राजनीतिक दल के नेताओं, प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रियों, संसद के सदस्यों से मिलना, iii) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रैलियां, प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान आयोजित करना और राष्ट्रीय स्तर, iv) क्षेत्रीय और डायोकेसन स्तर पर आयोगों की स्थापना के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एनीमेशन कार्य, v) संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षाओं के लिए कोचिंग पर विशेष जोर देने के साथ रोजगार के लिए गहन कोचिंग, vi) समर्थन प्रासंगिक सामग्री और पुस्तकें प्रदान करके सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका मामले, vii) राष्ट्रीय दलित ईसाई परिषद (NCDC) नामक दलित ले आंदोलन के साथ सहयोग करना, viii) राष्ट्रीय चर्च परिषद (NCCI) के सहयोग से संयुक्त रूप से काम करना दलित ईसाइयों के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति (NCCDC) के बैनर तले।

देश भर में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के अपने सभी प्रयासों के सामने भारतीय चर्च की दोहरी बातें गंभीर सवाल खड़े करती हैं। एक ओर, अनुसूचित जाति के लोगों से वादा किया जा रहा है कि उन्हें किसी भी तरह के भेदभाव का सामना

नहीं करना पड़ेगा, जबकि दूसरी ओर धर्मांतरण के बाद उन्हें अतिरिक्त समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस गंभीर दोहरे बोल और विरोधाभास के कारण भारतीय चर्च बेनकाब हो गया है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के दृष्टिकोण से गंभीरता से संबोधित करने की आवश्यकता है। भारत में ईसाइयों की आबादी बढ़ाने के चर्च के स्पष्ट इरादे को परोक्ष उद्देश्यों के साथ देखा जाता है।

व्यक्तिगत कानून

दोनों अब्राहीम धर्म – इस्लाम और ईसाई धर्म – जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं। वास्तव में, अनुसूचित जाति के लिए अन्य धर्मों में धर्मांतरित होने के लिए जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता की अनुपस्थिति के दो निर्णायक कारण थे। इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रसार में शामिल लोग हमेशा अनुसूचित जाति के लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें किसी भी तरह के भेदभाव और छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ेगा। विडंबना यह है कि अब दो अब्राहमिक धर्म जाति के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

यह एक बड़ा विरोधाभास है कि ईसाई और मुसलमान जाति–आधारित आरक्षण की मांग करते हैं, जबकि जाति को कोई धार्मिक स्वीकृति नहीं है और वे अपने–अपने धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होना चाहते हैं। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि मुसलमान कभी भी अपने धार्मिक मामलों में किसी बाहरी पक्ष के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ईसाई पर्सनल लॉ पर शायद ही कभी बहस होती है। क्रिश्चियन पर्सनल लॉ की उत्पत्ति ब्रिटिश शासन में हुई थी क्योंकि इसे १९वीं शताब्दी में अधिनियमित किया गया था। ईसाई पर्सनल लॉ जो मुख्य रूप से विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित है। क्रिश्चियन पर्सनल लॉ की अलग–अलग विशेषताओं को एक प्रावधान से आंका जा सकता है, जो

इंगित करता है कि कैसे ईसाई अपनी धार्मिक पहचान के प्रति संवेदनशील और सुरक्षात्मक हैं। क्रिश्चियन पर्सनल लॉ के अनुसार, एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे की सहमति के बिना दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन को तलाक के लिए एक प्रमुख आधार माना जाता है। यह अन्य धर्मों के प्रति ईसाइयों के असहिष्णु रवैये को दर्शाता है। यह एक मुस्लिम प्रथा की तरह है जिसमें एक दूल्हा या दुल्हन, अगर मुस्लिम नहीं है, तो निकाह से पहले उन्हे इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता है।

ईसाइयों की तरह मुसलमानों का भी अपना कानून है। भारत में सभी मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, १९३७ द्वारा शासित हैं। यह कानून मुसलमानों के बीच विवाह, उत्तराधिकार, विरासत और दान से संबंधित है। न्यायपालिका के हस्तक्षेप और केंद्र सरकार की पहल के कारण ट्रिपल तलाक की प्रथा पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है लेकिन अन्य कारक शरीयत द्वारा चलाए जा रहे हैं। मुसलमान अपने धार्मिक मामलों को लेकर अति संवेदनशील हैं। भारत ने गंभीर संघर्ष देखा है क्योंकि मुसलमान कभी भी अपने धार्मिक मामलों में, यहां तक कि राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करते हैं। शाह बानो का मामला एक उदाहरण के रूप में खड़ा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार ने मुसलमानों के सामने खुद को पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया।

दोनों अब्राहमिक धर्म अपनी अलग धार्मिक पहचान बनाए रखना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत कानूनों पर कोई समझौता नहीं चाहते हैं, बल्कि आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, जो कि हिंदुओं में निराश लोगों के लिए है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४४ के विशिष्ट प्रावधान के बावजूद दोनों धर्म समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विरोध करते रहे हैं। अनुच्छेद ४४ कहता है, राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यूसीसी भारत के लिए एक कानून बनाने की मांग करता

है, जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा। यूसीसी को लागू करने के किसी भी प्रयास का ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा घोर विरोध किया जाता है क्योंकि वे न केवल अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखना चाहते हैं बल्कि अपने धर्मों का प्रसार करना चाहते हैं। वे अपनी अल्पसंख्यक स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं और कुछ संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करके अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। वे धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव का लाभ पाने के लिए उत्सुक हैं, जो उनके धर्म की विशेषता कभी नहीं थी। यह सब हिंदुओं के हितों की कीमत पर हो रहा है, जो स्वभाव से सहिष्णु हैं।

कानून एवं व्यवस्था

अनुसूचित जाति के लोगों को इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों ने लुभाया है। धर्मांतरण के लिए बलप्रयोग, मिथ्या कथन, भ्रामक जानकारी, दैवीय श्राप और बाहुबल/धनबल जैसे विभिन्न हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हिंदुओं में विभाजन और जनसंख्या में वृद्धि धर्मांतरण के पीछे दो स्पष्ट उद्देश्य हैं। हिंदुओं से दुश्मनी पैदा करने के मकसद से रणनीतिक गठजोड़ किया जा रहा है। ये गठजोड़ केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि संस्कृति, इतिहास, शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरशाही सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में बने हैं।

हालाँकि, इन प्रयासों के फल नहीं मिले हैं क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों की जड़ें भारत की मिट्टी में बहुत मजबूत हैं। अनुसूचित जाति के लोगों में इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति स्वाभाविक स्नेह और प्रेम नहीं है क्योंकि दोनों धर्मों को विदेशी के रूप में देखा जा रहा है।

जमीनी हकीकत अन्यथा निहित स्वार्थों द्वारा पेश की गई तस्वीर के विपरीत है। जबकि मुस्लिम और ईसाई अपने धार्मिक मामलों में बहुत कठोर और रूढ़िवादी

हैं, अनुसूचित जाति के लोग अधिक उदार हैं और परिवर्तन के लिए खुले हैं। वास्तविकता यह है कि अनुसूचित जातियों और मुसलमानों/ईसाइयों के बीच संबंध कभी भी सौहार्दपूर्ण नहीं रहे और कानून व्यवस्था के लिए बड़ी समस्या बन गए। तनाव के कारण प्रथाओं और रीति–रिवाजों, प्रार्थना, मूर्ति पूजा, जुलूसों, त्योहारों और यहां तक कि अंत्येष्टि के बीच भारी अंतर हैं। अनुसूचित जाति के लोग इस्लाम और ईसाई धर्म के साथ कोई साझा हित और एजेंडा साझा नहीं करते हैं। दोनों अब्राहमिक धर्म स्वभाव से आक्रामक हैं। सामाजिक जीवन में दूसरों पर हावी होने की इनकी आदत होती है, जो अनुसूचित जाति के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। अनुसूचित जाति के लोगों को गर्व है कि डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने न तो इस्लाम और न ही ईसाई धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दी, जिसकी जड़ें भारत की धरती में दृढ़ और मजबूत हैं।

अनुसूचित जाति के लोग और दो अब्राहीम धर्मों के बीच तनाव, यदि आरक्षण को कवरों तक बढ़ाया जाता है, तो यह गंभीर रूप ले लेगा। अनुसूचित जाति के लोग इसे स्वीकार करने की संभावना नहीं है क्योंकि वे इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रत्यक्ष शिकार होंगे। भारत में २० करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी है, जो मुख्य रूप से छह लाख गांवों में फैली हुई है। अनुसूचित जाति के लोगों और इस्लाम/ईसाईयों के बीच तनाव की भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

उपसंहार

धर्मान्तरित लोगों के लिए आरक्षण का विस्तार राष्ट्रीय चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यह न केवल जनसांख्यिकी में भारी बदलाव लाएगा बल्कि सामाजिक असंतुलन का कारण बनेगा। इसे विदेशियों द्वारा भारत की प्राचीन संस्कृति और भूमि पर कब्जा करने के अंतहीन प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने तीन दशक पहले संभावित खतरे की आशंका जताई थी। १९९० में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (एबीपीएस) ने बौद्धों को आरक्षण देने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। हालाँकि, आरएसएस के एबीपीएस द्वारा पारित एक प्रस्ताव ने ईसाइयों द्वारा धर्मांतरित ईसाइयों को आरक्षण देने की मांग पर आश्चर्य व्यक्त किया। एबीपीएस को यह कहते हुए दुख हुआ कि कुछ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री धर्मांतरित ईसाइयों के लिए आरक्षण की मांग के प्रति सहानुभूति रखते थे।

आरएसएस के प्रस्ताव में कहा गया है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उनकी अज्ञानता का फायदा उठाकर या प्रलोभन देकर ईसाई या इस्लाम में धर्मांतरित करने के पीछे का मकसद धार्मिक से अधिक राजनीतिक है। इस उद्देश्य के लिए वे अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक मूल्य प्रणालियों को नष्ट करके उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा से दूर करने का प्रयास करते हैं। अन्यथा, जाति के आधार पर उनकी रियायतों की मांग करने का कोई कारण नहीं है, जब वे उच्च या निम्न, अस्पृश्य या अछूत के विचार से ऊपर होने का दावा करते हैं।

मांग के पीछे का कारण बताते हुए, आरएसएस के प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण उनके द्वारा (ईसाई) अपने धर्मांतरण के मिशन में एक बड़ी बाधा के रूप में माना जा रहा है। इसमें कहा गया है, इस तरह ईसाई या इस्लाम में धर्मांतरण को किसी भी परिस्थिति में बौद्ध धर्म में

परिवर्तन के बराबर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि भगवान बुद्ध और उनकी मूल्य प्रणाली हमारी मुख्य सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का एक अभिन्न अंग है।

यह कहते हुए कि संविधान निर्माताओं ने इन रियायतों की परिकल्पना केवल हिंदू समाज में प्रचलित जाति–आधारित भेदभाव और असमानता को दूर करने के लिए की थी, आरएसएस के प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ईसाइयों को आरक्षण का विस्तार, हिंदू समाज के वास्तव में जरूरतमंद वर्गों को वंचित कर सकता है। रियायत की, क्योंकि वे शैक्षिक रूप से उन्नत ईसाई धर्मान्तरित लोगों द्वारा घेर लिए जा सकते हैं।

तीन दशक पहले आरएसएस ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि वह कुछ ईसाई संगठनों के हथकंडों के आगे न झुके और कोई भी गलत कदम उठाने से बाज आए, जिससे विदेशी धन से पोषित ईसाई मिशनरियों के राष्ट्र–विरोधी मनसूबों को बल मिले और इस तरह नई समस्या को बढ़ावा मिले।

पिछले तीन दशकों के घटनाक्रमों की श्रृंखला ने यह साबित कर दिया है कि आरएसएस इस परिदृश्य का अनुमान लगाने में कितना सही था। स्थिति थोड़ी और जटिल हो गई है क्योंकि धर्मांतरित मुस्लिम, धर्मांतरित ईसाइयों के साथ आरक्षण की मांग कर रहे हैं। यह जागने का समय है।

''अनुसूचित जातियां हिंदू समुदाय के पिछड़े वर्ग थे, जो अस्पृश्यता के प्रथा से विकलांग थे और अस्पृश्यता की इस बुरी प्रथा को किसी अन्य धर्म द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी और इसलिए हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म से संबंधित अनुसूचित जाति का सवाल ही नहीं उठता था।'' – डॉ. बी आर अंम्बेडकर संविधान सभा– ४ अप्रैल १९४९.

''किसी भी भारतीय ईसाई को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा।'' भारत सरकार (अनुसूचित जाति) आदेश, १९३६.

''हिंदू धर्म से अलग धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। बशर्ते कि पंजाब या पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ में रहने वाले रामदासी, कबीरपंथी, मजहबी या सिकलीगर जातियों के प्रत्येक सदस्य को उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति का सदस्य माना जाएगा, चाहे वह हिंदू धर्म को मानता हो या सिख धर्म को। ''१९५७ राष्ट्रपति आदेश.

''हिन्दू धर्म में प्रचलित छुआछूत के कारन इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण दिए जाने का विरोध कई अनुसूचित जाति संगठनो ने किया है। कई मुस्लिम संगठनो ने कई राज्यों में भी इसका विरोध करते हुए कहा है की मुसलमानों को अनुसूचित जाति का नहीं माना जा सकता है। उनको अनुसूचित जाति में ना रख कर अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में देखा जाएं और उसके अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के लाभ उन्हे दिए जाए। इस आधार पर अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग तर्कसंगत नहीं है।'' केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका अक्तूबर २०२२.

ISBN : 978-93-94486-01-0